



04 - खनन माफिया  
और सरकार



05 - इस कानून का उद्देश्य  
वर्तमान प्रणाली को  
बदलना

A Daily News Magazine

भोपाल  
सोमवार, 06 जुलाई, 2026



06 - विसल ऑफ होप:  
संदीप त्रेहन



07 - एमपी के 24 जिलों  
पर मंडराया सूखे का  
खतरा

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित



वर्ष 23, अंक 304, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2

# सूचना

subhasaverenews@gmail.com  
facebook.com/subhasaverenews  
www.subhasavere.news  
twitter.com/subhasaverenews

## सुप्रभात

तुम भी कुछ बोलो तो बात कहीं  
बातों में रस घोलो तो बात कहीं

होने लगी हैं बातें रजिशा की  
तुम मुझे थाम लो तो बात कहीं

सच है तुम्हारा रूठना, मनाना  
चुप के ताले खोलो तो बात कहीं

तुम मुझे खुद अपना ही समझो  
सभी को साध लो तो बात कहीं

लफज हैं तो संवाद होना चाहिए  
दिल में हों जज्बात तो बात कहीं।

- अरुण सातले

## प्रसंगवश

# जस्टिस जामदार की टिप्पणी तो हर सरकार को लेकर है..

शीतल पी. सिंह

लो | कर्तव्य, संविधान और न्यायपालिका के सामने खड़ा एक असहज प्रश्न है- 'क्या सभी नागरिकों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है? अगर लोग विरोध करेंगे तो उन पर मुकदमे कर दिए जाएंगे? क्या नागरिक 'मुर्दाबाद' जैसे नारे भी नहीं लगा सकते?' बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति माधव जामदार की यह टिप्पणी उस बेचैनी की अभिव्यक्ति थी जिसे पिछले कुछ वर्षों से देश के अनेक नागरिक, पत्रकार, छात्र, किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और संवैधानिक विशेषज्ञ अलग-अलग शब्दों में व्यक्त करते रहे हैं।

जिस मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी आई, उसमें एक राजनीतिक कार्यकर्ता के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शन और नारेबाजी के आधार पर निष्कासन (Externment) की कार्रवाई की गई थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पूछा कि यदि कोई नागरिक शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के खिलाफ नारे लगाता है तो क्या यह इतना बड़ा अपराध है कि उसे अपने ही क्षेत्र से बाहर कर दिया जाए? यह प्रश्न केवल उस एक मामले तक सीमित नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप पर एक व्यापक बहस का द्वार खोलता है।

भारत का संविधान केवल सरकार बनाने का दस्तावेज नहीं है। यह नागरिकों की स्वतंत्रता का भी घोषणापत्र है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होकर विरोध करने का अधिकार देता है। इन अधिकारों पर कुछ 'युक्तिरहित प्रतिबंध' लगाए जा सकते हैं, लेकिन संविधान की मूल भावना यही है कि सत्ता की आलोचना लोकतंत्र का अभिन्न अंग है।

यदि नागरिक सरकार की आलोचना कर सकता है, यदि वह मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध नारे लगा सकता है, यदि वह धरना दे सकता है, जापन दे सकता है और सरकार से जवाब मांग सकता है, तो लोकतंत्र जीवित है। लेकिन यदि यही कार्य धीरे-धीरे मुकदमों, गिरफ्तारियों, प्रशासनिक प्रतिबंधों और भय का कारण बनने लगे तो लोकतंत्र का ढांचा भले बना रहे, उसकी आत्मा कमजोर होने लगती है। पिछले एक दशक में भारत में अनेक ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिन्होंने इस प्रश्न को और गंभीर बना दिया है।

नागरिकता संशोधन कानून (सीए) के विरोध में हुए आंदोलनों के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। कुछ मामलों में कठोर आतंकवाद-रोधी कानूनों का भी उपयोग किया गया। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि सत्ता में आने के बाद लगभग हर दल आलोचना के प्रति पहले की तुलना में कम सहिष्णु हो जाता है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि लोकतंत्र की गुणवत्ता का मूल्यांकन इसी कसौटी पर होता है कि क्या सत्ता आलोचना को स्थान देती है या उसे खतरे के रूप में देखने लगती है।

भारत का स्वतंत्रता आंदोलन स्वयं असहमति का सबसे बड़ा आंदोलन था। 1975 का आपातकाल इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण अध्याय है। उस दौर का सबसे बड़ा सबक यही था कि लोकतंत्र केवल चुनावों से सुरक्षित नहीं रहता; उसे स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस और निर्भीक नागरिक समाज की भी आवश्यकता होती है। इसी कारण आपातकाल के बाद भारतीय लोकतंत्र ने यह स्वीकार किया कि नागरिक स्वतंत्रताओं

की रक्षा किसी भी सरकार से अधिक महत्वपूर्ण है। आज प्रश्न यह नहीं है कि कौन-सी पार्टी सत्ता में है।

प्रश्न यह है कि क्या भारतीय लोकतंत्र धीरे-धीरे उस दिशा में बढ़ रहा है जहाँ सरकार की आलोचना और राष्ट्र-विरोध के बीच की रेखा जानबूझकर धुंधली की जा रही है? क्या सरकार और राष्ट्र को एक ही मान लेने का आग्रह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है? यदि कोई नागरिक 'सरकार मुर्दाबाद' कहता है, तो क्या वह 'भारत मुर्दाबाद' कह रहा है? संविधान का उत्तर स्पष्ट है- नहीं। सरकारें अस्थायी हैं, राष्ट्र और संविधान स्थायी हैं। यहाँ पर न्यायमूर्ति माधव जामदार की टिप्पणी एक बड़े संवैधानिक प्रश्न में बदल जाती है। यदि शांतिपूर्ण राजनीतिक नारे भी प्रशासनिक कार्रवाई का आधार बनने लगे, तो क्या नागरिकों का लोकतांत्रिक आत्मविश्वास प्रभावित नहीं होगा? क्या भय और लोकतंत्र साथ-साथ चल सकते हैं?

इन प्रश्नों का उत्तर केवल किसी एक मुकदमे में नहीं मिलेगा। भारतीय न्यायपालिका ने भी समय-समय पर लोकतंत्र की इसी मूल भावना को दोहराया है। 1962 में केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि सरकार की कठोर आलोचना या उसके विरुद्ध तीखी भाषा का प्रयोग अपने-आप में राजद्रोह नहीं है। इस फैसले ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि लोकतंत्र में सरकार और राष्ट्र एक ही चीज नहीं हैं। सरकार की आलोचना राष्ट्र-विरोध नहीं हो सकती। 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में विचारों की विविधता और असहमति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है।

2018 में मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत

संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विरोध-प्रदर्शन लोकतांत्रिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। राज्य का दायित्व केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अवसर उपलब्ध कराना भी है। यही संवैधानिक संतुलन है। 'और शायद सबसे अधिक उद्धृत होने वाली टिप्पणी न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की उस पीठ से आई जिसमें उन्होंने कहा था- 'असहमति लोकतंत्र का संपूर्ण वास्तव है। यदि उसे बंद कर दिया जाए तो लोकतंत्र का प्रेशर कुकर फट सकता है।' यह केवल एक साहित्यिक वाक्य नहीं था। यह भारतीय संविधान के दर्शन का सार था। यही कारण है कि न्यायमूर्ति माधव जामदार की हलिया टिप्पणी को केवल एक अदालत की टिप्पणी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कोई नया सिद्धांत नहीं दिया। उन्होंने केवल संविधान की उसी मूल भावना की याद दिलाई जिसे सर्वोच्च न्यायालय कई दशकों से दोहराता रहा है।

चोरी: क्या RSS के चेहरे से नैतिकता का नकाब उतर गया है लेकिन प्रश्न केवल अदालतों का नहीं है। यही हमारे लोकतांत्रिक व्यवहार का भी है। आज सार्वजनिक जीवन में एक नया चलन दिखाई देता है। सरकार की आलोचना करने वाला व्यक्ति तुरंत किसी राजनीतिक खांचे में खल दिया जाता है।

इसलिए न्यायमूर्ति माधव जामदार का प्रश्न केवल महाराष्ट्र सरकार से नहीं है। यह हर उसह हर उस सरकार से है जो आज सत्ता में है या कल सत्ता में आएगी। क्योंकि सत्ता का स्वभाव बदल सकता है, लेकिन संविधान का चरित्र नहीं बदलना चाहिए।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

# मिशन यूपी फतह की तैयारी में जुटी बीजेपी

केशव भी मौजूद, सभी ने साथ में बैठकर आम खाया



लखनऊ (एजेंसी)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रविवार दोपहर 2 बजे लंच के लिए डिटी सीएम ब्रजेश पाठक के घर पहुंचे। उनके साथ सीएम योगी, डिटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी भी पहुंचे। ब्रजेश पाठक खुद प्लेट में आम लेकर

पहुंचे। फिर चारपाई पर साथ बैठकर सभी ने आम खाया। इससे पहले, नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात की। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद, सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, अपना दल (एस) की प्रमुख अनुप्रिया पटेल के पति अशीष पटेल और रालोद महासचिव त्रिलोक त्यागी से 10-10 मिनट बातचीत की। मीटिंग के बाद संजय निषाद, राजभर और अशीष पटेल ने बताया कि सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई।

## योगी ने प्रदेश की पहचान बदलने का काम किया

यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा- आज यूपी में ब्रह्मसंघ मिसाइल बन रही है। आज भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत हर चीजों में आगे बढ़ रहा है। योगी ने प्रदेश की पहचान बदलने का काम किया है। पहले वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया हुआ करता है। हमारी मां-बहन घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं। लेकिन, 9 साल के अंदर किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि उनकी तरफ आंख उठाकर देख सके। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर हमने दिया है। मैंने चुनाव लड़ता हूँ। मैं कार्यकर्ताओं के भावना जानता हूँ।

## योगीजी के डर से गुंडे-माफिया लुप लुप कर रहे

डिटी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा- 2017 से पहले यूपी में गुंडाराज था। बहू-बेटी की इज्जत, आबरू खतरे में थी। अब कोई माफिया बचा है क्या। जब हम लोग छोटे थे, तो शोले पिक्चर देखकर चर्चा होती थी, सो जाओ नहीं तो गबबर आ जाएगा। आज गुंडा-माफिया अपने घर में लुप, लुप कर रहे हैं। उन्हें डर है कि योगी जी आ जाएंगे। सीएम योगी ने यूपी में कानून राज स्थापित किया है। डिटी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं से कहा- मोदी जी कहते हैं कि देश में चार जातियां हैं। गरीब, महिला, किसान, युवा।

# जिसने हमारे इमाम को मारा, वो जिंदा क्यों है



खामेनेई के अंतिम संस्कार में ट्रंप के खिलाफ लगे भड़काऊ नारे

तेहरान (एजेंसी)। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार कार्यक्रम चल रहा है। इस शोक कार्यक्रम को लेकर ईरान की राजधानी तेहरान में लाखों लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। इन भारी भीड़ के बीच एक कलाकार ने ट्रंप का नाम लिए बिना उनके हत्या की मांग की। रविवार को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में एक कलाकार ने अपने इमाम की हत्या करने वाले व्यक्ति की मीत की मांग की, जिस पर तेहरान में एकत्रित सैकड़ों हजारों शोक संतप्त लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं।

# एमपी में बनेंगी मिसाइलें, गोला बारूद और बम शिवपुरी में सीएम और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अदाणी डिफेंस प्लांट की रखी नींव



भोपाल/शिवपुरी (नप्र)। मध्य प्रदेश में अब अत्याधुनिक मिसाइलें बनेंगी। शिवपुरी में अदाणी अत्याधुनिक डिफेंस मैनुफैक्चरिंग प्लांट का सीएम मोहन यादव ने शिलान्यास किया है। इस प्लांट में अत्याधुनिक मिसाइलें बनाई जाएंगी। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी प्लांट है।

2500 करोड़ रुपए का होगा निवेश- सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2,500 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के मैनुफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने 211 करोड़ से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया। शिलान्यास से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अदाणी समूह द्वारा प्रदर्शित अत्याधुनिक हथियारों और रक्षा उपकरणों के मॉडलों का अवलोकन किया है।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के मैनुफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया गया। फैक्ट्री में गोला-बारूद, हार्डटेक हथियार, मिशन-रेडी मिसाइलें और हार्डटेक डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। मैनुफैक्चरिंग प्लांट में करीब 10 हजार लोगों को नौकरियां मिलेंगी।

## सीएम मोहन बोले- महाराज ने थोड़ा ज्यादा मक्खन लगा दिया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मांगों पर कहा- आज महाराज की आवाज कुछ अलग ही नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे रोटी पर थोड़ा ज्यादा मक्खन लगा दिया हो। हालांकि, मांगों को स्वीकार करते हुए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि शिवपुरी में 100 फीट से अधिक ऊंची भगवान शिव की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही करीब 120 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना और नई तहसील को मंजूरी दी गई। यादव ने कहा कि एमपी में बनने वाली मिसाइलें 1000 किमी की दूरी तक दुश्मनों पर वार करेंगी। यह शिवपुरी के लिए ऐतिहासिक दिन है। शिवपुरी में अब रोजगार का नया मौका मिलेगा। करीब 4-5 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिवपुरी क्षेत्र के लिए यह बड़ी इंडस्ट्री है।

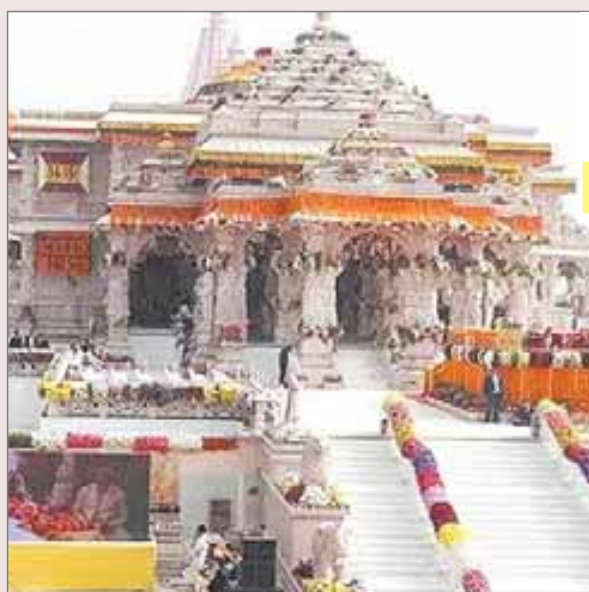
## सिंधिया बोले- युद्ध में शिवपुरी से हथियार और गोला-बारूद जाएंगे

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जब भी देश की रक्षा के लिए युद्ध होगा, तब शिवपुरी से हथियार और गोला-बारूद जाएंगे। यहाँ के युवाओं की मेहनत से बने हथियार दुश्मन का सीना चीरेगा। गोला-बारूद दुश्मन को परास्त करेंगे। उन्होंने शिवपुरी के लिए सीएम मोहन से 4 मांगें भी कीं।

अदाणी समूह के डायरेक्टर जीत अदाणी ने कहा- समूह के चेयरमैन ने मध्य प्रदेश में 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। यह निवेश पंप हाइड्रो स्टोरीज, सीमेंट, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स और थर्मल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। अदाणी ग्रुप का लक्ष्य 2030 तक मध्य प्रदेश में करीब 1 लाख 20 हजार रोजगार उपलब्ध कराना है। सीएम ने कहा एमपी में निवेश के द्वार खुल चुके हैं जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। शिलान्यास से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदर्शनी टेंट में रखे हथियारों, मिसाइलों और अन्य डिफेंस इक्विपमेंट का जायजा लिया।

# राममंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ऐवशन हुआ

● पांच आरोपियों से पूछताछ करने जेल पहुंची पुलिस ● एमपी कार्यालय में पोस्टर-चंदा चोरों का प्रवेश वर्जित



अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के पांच आरोपियों से पूछताछ के लिए पुलिस रविवार दोपहर 1.50 बजे जेल पहुंची। राम मंदिर चोरी के 8 आरोपी जेल में बंद हैं। चढ़ावा चोरी के 3 आरोपियों से पुलिस पहले ही पूछताछ कर चुकी है। जिन आरोपियों से रविवार को पूछताछ होनी है, उनमें रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडेय शामिल हैं। इधर, अयोध्या जेल में शनिवार को सभी आरोपियों को अलग-अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। पहले सभी एक बैरक में थे। पुलिस को शंका थी कि ये सभी आपस में मारपीट कर सकते हैं या कोई साजिश रच सकते हैं। इस बीच, लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर रविवार को एक पोस्टर लगाया गया। पोस्टर पर लिखा है- 'चंदा चोर पार्टी का प्रवेश वर्जित है।'

## दोषियों को बख्शा नहीं जाएगी: नितिन नवीन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर शनिवार को पहली बार बयान दिया। उन्होंने लखनऊ में कहा- जो हुआ, वह गलत है। इससे जनता में गलत संदेश गया है। यह विपरीत परिस्थिति है और विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, जांच पूरी होने पर एसआईटी 15 के बाद एफआईआर दर्ज करेगी।

## पहली बार राममंदिर की बैठक लीड नहीं करेंगे चंपत राय

अयोध्या श्रीराम ट्रस्ट की 6 जुलाई को होने वाली बैठक कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि लीड करेंगे। बैठक मणिराम दास छावनी में अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में होगी। बतौर ट्रस्टी चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा को भी इस बैठक में बुलाया गया है। इसमें ट्रस्ट के सदस्य बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे कि महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर किया जाए या नहीं।



## संक्षिप्त समाचार

## मुझे रोकना है तो पहले मारना पड़ेगा

- ममता बनर्जी बोली-गद्दारी की भी एक सीमा होती है

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में जारी बगवत के बीच ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी का चुनाव चिह्न नहीं जाएगा। अगर मुझे रोकना है तो मुझे मारना पड़ेगा। ममता ने बागी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा, 'अगर हिम्मत है तो खुलकर बीजेपी में शामिल हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खत्म हो गई हूँ। मैं जनता के बीच पार्टी का चुनाव चिह्न लेकर जाऊंगी, मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता।' उन्होंने आरोप लगाया कि बागी नेता अब खुलकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ममता ने कहा, 'गद्दारी की भी एक सीमा होती है।' ममता का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पार्टी के 20 सांसद और 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं। शनिवार को टीएमसी की पश्चिम बंगाल अध्यक्ष चंद्रिका भट्टाचार्य ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में वह बागी गुट के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतुब्रत बनर्जी के साथ नजर आईं। ममता का साथ छोड़कर अलग गुट बागी विधायक और सांसद फिलहाल भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं।



हांगकांग एयरपोर्ट पर फंस गया एक भारतीय परिवार

## हांगकांग एयरपोर्ट पर फंस गया एक भारतीय परिवार

- आंध्र प्रदेश के मंत्री लोकेश ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मदद की अपील

अमरावती (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने रविवार को विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से हांगकांग एयरपोर्ट पर फंसे एक तेलुगु परिवार की तुरंत मदद करने की अपील की।



की। तेलुगु परिवार का पासपोर्ट खो गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे और मानव संसाधन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेश मंत्री से अपील की। राजेश्वरी बोला नाम की एक महिला ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री लोकेश को सोशल मीडिया पर टैग करके उनसे मदद मांगी। इसके बाद, उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद मांगी।

## दत्तात्रेय होसबाले के बयान से पूरी तरह सहमत हूँ

- राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आया मोहन भागवत का बयान

नागपुर (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि वह राम मंदिर चढ़ावे के मामले पर संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले की बात से सहमत हैं। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए भागवत ने कहा, होसबाले जी का बयान देखिए... मेरी भी वही प्रतिक्रिया है। आरएसएस प्रमुख ने यह प्रतिक्रिया



एक कार्यक्रम के दौरान दी, जब उनसे राम मंदिर चढ़ावे के विवाद पर उनकी राय पूछी गई। शुक्रवार को एक बयान में होसबाले ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के कथित दान चोरी ने पूरे समाज की भावनाओं और आस्था को गहरा ठेस पहुंचाई है और यह पक्का करने की मांग की कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाए उसे कड़ी सजा मिले। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू-विरोधी और देश-विरोधी ताकतें इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का फायदा उठाकर हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं और हिंदू समाज से इस मुश्किल समय में ऐसी साजिशों को नाकाम करने के लिए जरूरी सब्र और संयम दिखाने को कहें।

## घाटी में बड़ी सफलता, 2 आतंकी ढेर

## एक पहलगांम हमले के बाद बनी हिट लिस्ट में शामिल था, शोपियां में 3 घंटे चला एनकाउंटर

शोपियां (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के शोपियां के सैदपोरा इलाके में शनिवार शाम से चल रही मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकीयों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षाबलों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के टॉप ऑपरेटिव थे। एक आतंकी जाकिर अहमद गनी उन 14 आतंकीयों की लिस्ट में शामिल था, जिसे पहलगांम हमले के बाद खुरिफा एजेंसियों ने जारी किया था। दूसरा आतंकी जाकिर का साथी लतीफ भट्ट है। सुरक्षाबलों को शोपियां के सैदपोरा पाथीन के पास छानपोरा इलाके में आतंकीयों के छिपे होने की खबर मिली थी। घेराबंदी के दौरान जब जवान आतंकीयों के ठिकाने के करीब पहुंचे तो उन्होंने फायरिंग कर दी। मुठभेड़ 4 जुलाई की शाम 7.45 बजे शुरू हुई थी। अंधेरे के कारण एनकाउंटर और सच ऑपरेशन रात में रोक दिया गया था। अभी तक आतंकीयों के शव भी बरामद नहीं हुए हैं।



दावा-कुलगाम का रहने वाला था जाकिर सूत्रों के मुताबिक, कुलगाम के मुतलहम गांव के रहने वाले जाकिर अहमद गनी को सुरक्षा बलों ने कल दक्षिण कश्मीर के जिलों में दूसरे आतंकीयों के साथ ट्रैक किया था। जाकिर का नाम पाकिस्तान से जुड़े कई आतंकी हमलों से भी जुड़ा था।

## 14 लोकल आतंकीयों में 9 मारे गए, अब 5 की तलाश

अगर जाकिर गनी की मौत की पुष्टि हो जाती है तो 9वां आतंकी होगा, जिसे सुरक्षाबलों ने मार गिराया है। जिन 14 आतंकीयों की लिस्ट जारी की थी, जाकिर गनी को मिलाकर उनमें से अब तक 9 मारे जा चुके हैं। 16 आतंकी मई 2025 में शोपियां और पुलवामा में एनकाउंटर के दौरान मारे गए थे।

## बारिश ने दिखाया रौद्र रूप, नदी बन गई सड़कें

भीषण बारिश से महाराष्ट्र और गुजरात में बिगड़े हालात

## वॉटरफॉल में फंसे 100 टूरिस्ट, रस्सी के सहारे रेस्क्यू • वसई में 20 कारें डूबीं, छत्तीसगढ़ में घरों में पानी घुसा

मुंबई (एजेंसी)। देश के कई राज्यों में मानसून ने रफतार पकड़ ली है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जेनिथ वॉटरफॉल में अचानक पानी का लेवल बढ़ गया। जिसमें 100 टूरिस्ट फंस गए, रस्सी की मदद से उन्हें निकाला गया। महाराष्ट्र में वसई के नालासोपारा में सड़क नदी जैसी बन गई। करीब 20 कारें उसमें डूब गईं। मुंबई में 64 पेड़ गिर गए और 8 मकानों की दीवारें ढह गईं। गुजरात के जूनागढ़ में कई इलाकों में 4 फीट तक पानी भर गया। सड़क पर नाव चलानी पड़ रही है। भावनगर में एक कार पानी में बह गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शनिवार रात आधे घंटे के भीतर ही 30 मिमी पानी बरसा। टाटीबंध में घरों में पानी भर गया। एक

अधिकारी ने बताया कि पीड़ित युवस कुंडवाला को मलबे से निकालकर फौजिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड, पुलिस, बेस्ट और नगर निगम के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव व साफ-सफाई का काम किया। यह घटना 30 जून को चेंबूर में चलती स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 वर्षीय लड़के की मौत और कई अन्य लोगों के घायल होने की घटना के कुछ दिनों बाद हुई है।



## छिंदवाड़ा-उमरिया में बारिश, श्योपुर में दुकानों में पानी भरा



मध्य प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। रविवार सुबह छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में पानी गिरा। दोपहर 12 बजे के बाद उमरिया में तेज बारिश हुई। श्योपुर में आधे घंटे की बारिश से दुकानों में पानी भर गया। भोपाल में धूप-छांव वाला मौसम है। इंदौर समेत कई जिलों में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के आधे हिस्से में अति भारी या भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में सबसे ज्यादा अस्तर रहेगा।

## मशहूर पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन

- राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार

रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन को वैश्विक पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन हो गया। वे 70 साल की थीं। उन्होंने शनिवार रात 3.15 बजे रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ समय से बीमार थीं। भारतीय लोक कला में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। रविवार सुबह 11 बजे तीजन बाई के शव को उनके पैतृक गांव गनियारी लाया गया।



राजेश गाबा 'पिंस'

आज भारतीय लोक संस्कृति का एक युग मौन हो गया। पंडवानी की वह अनुगूंज, जिसने महाभारत को केवल सुनाया नहीं, बल्कि मंच पर सजीव कर दिया, आज सदा के लिए शांत हो गई। पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण से अलंकृत, विश्वविख्यात लोकगायिका तीजन बाई का निधन केवल एक कलाकार का जाना नहीं है, बल्कि भारतीय लोक परंपरा के एक ऐसे अध्याय का अंत है, जिसे आने वाली पीढ़ियाँ श्रद्धा से पहेंगी और याद करेंगी। तीजन बाई केवल पंडवानी नहीं गाती थीं, वे महाभारत को जीती थीं। सच भी यही था। जैसे ही उनके हाथों में रंग-बिरंगे फुंदनों से सजा तापपूरा आता, वह केवल एक वाद्य यंत्र नहीं रहता था। कभी वही दुःशासन की भुजा बन जाता, कभी अर्जुन का रथ, कभी भीम की गदा, तो कभी द्रौपदी की पीड़ा। उनकी आंखें, उनकी आवाज, उनकी देहभाषा और उनकी ऊर्जा श्रोताओं को हजारों वर्ष पीछे महाभारत के उस कालखंड में ले जाती थी, जहाँ धर्म-अधर्म, वीरता, करुणा, क्रोध, छल, प्रतिशोध और मानवीय संवेदनाओं का विराट संसार जीवंत हो उठता था। उन्होंने पंडवानी को गांव की चौपाल से निकालकर विश्व के प्रतिष्ठित मंचों तक पहुंचाया। छत्तीसगढ़ की मिट्टी की खुशबू को उन्होंने दुनिया के अनेक देशों में फैलाया। यही कारण है कि भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण और अंततः देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मविभूषण से सम्मानित किया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, डी.लिट. सहित अनेक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मानों ने उनके योगदान को स्वीकार किया, लेकिन सच तो यह है कि सबसे बड़ा सम्मान उन्हें करोड़ों श्रोताओं के प्रेम के रूप में मिला। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। बचपन में स्कूल नहीं जा सकीं, समाज ने उन्हें ठुकराया, निजी जीवन में अपार दुख झेले, दोनों बेटों को खोने का असहनीय दर्द सहा, बीमारी और पक्षाघात ने उन्हें शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया। फिर भी उन्होंने कभी अपनी लोककला के प्रति समर्पण नहीं छोड़ा। उनके जीवन ने यह सिद्ध किया कि सच्चा कलाकार सम्मान से नहीं, साधना से बड़ा बनता है। मेरे लिए यह समाचार केवल एक महान कलाकार के निधन का नहीं, बल्कि एक आत्मीय रिश्ते के टूटने जैसा है। मुझे सौभाग्य मिला कि कई बार उनसे मिलने, उन्हें सुनने और उनका साक्षात्कार करने का अवसर मिला। हर मुलाकात में उनका वही सहज, सरल और अपनापन से भरा व्यक्तित्व समाने आया। मंच पर वे जितनी विराट दिखाई देती थीं, मंच से उतरते ही उतनी ही सहज, खेमयवी और बिस्कुल

## प्रशांत किशोर होंगे बांकीपुर से जनसुराज के उम्मीदवार

## बिहार में नितिन नवीन की सीट पर दिलचस्प मुकाबला

प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने की बड़ी घोषणा

जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि इस बार चुनावी रण में सीधे प्रशांत किशोर ही पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जनसुराज की इस रणनीतिक घोषणा ने विपक्षी दलों के खेमों में हलचल तेज कर दी है।



नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई है सीट

बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की नौबत इसलिए आई क्योंकि यहां से लगातार चुनाव जीतते आ रहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और कददावर नेता नितिन नवीन अब राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। उनके संसद के उच्च सदन में जाने के बाद यह सीट रिक्त घोषित की गई थी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद पहली बार बांकीपुर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। चुनाव आयोग के शेड्यूल के मुताबिक इस सीट पर आगामी 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में नितिन नवीन की खाली हुई जगह को भरना नए उम्मीदवार के लिए बड़ी चुनौती होगी। प्रशांत किशोर के मैदान में आने से अब इस सीट पर लड़ते बहद दिलचस्प और त्रिकोणीय होने के आसार हैं। प्रशांत किशोर के खुद बांकीपुर से चुनाव लड़ने के फैसले ने बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है।

## जब पंडवानी की आवाज थम गई... और मेरी स्मृतियों में तीजन बाई हमेशा के लिए अमर हो गईं

अपने सहज अंदाज़ में मुस्कुराते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ी में कहा- 'बहुत अच्छा बोलते हो बेटे... खुश रहो। श्रीराम प्रभु तुम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें।' उनके ये शब्द मेरे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थे। उस दिन मैंने महसूस किया कि महानता का सबसे बड़ा परिचय विनम्रता होती है। करोड़ों लोगों की प्रिय कलाकार होने के बावजूद उनमें अहंकार का नामोनिशान नहीं था। उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनकी आत्मीयता आज भी मेरे मन में उसी तरह सुरक्षित है। आज जब उनके निधन का समाचार सुनता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पंडवानी का वह तानपूरा पहली बार सचमुच मौन हो गया हो। लेकिन क्या सच में कलाकार कभी चला जाता है? नहीं। जब-जब महाभारत की कोई पंडवानी शैली में गुँजती, जब-जब कोई कलाकार तानपूरा हाथ में लेकर भीम, अर्जुन, द्रौपदी और कृष्ण को मंच पर जीवंत करता, तब-तब तीजन बाई हमारे बीच होंगी। वे अपनी आवाज, अपनी शैली, अपनी साधना और अपनी अमिट विरासत के रूप में सदैव जीवित रहेंगी। भारतीय लोककला ने आज अपनी सबसे बुलंद आवाज खो दी है, लेकिन इतिहास ने एक अमर नाम पा लिया है। भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि। ऊँ शांति।

अपनी-सी लगती थीं। दिल्ली के एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक समारोह की वह शाम आज भी मेरी स्मृतियों में ताजा है। उस कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी मुझे मिली थी। उसी मंच पर तीजन बाई का सम्मान होना था और उनके पंडवानी गायन की प्रस्तुति भी। मंच से उनके जीवन परिचय का वाचन करने का अवसर भी मुझे मिला। जब मैंने उनके संघर्ष, साधना और उपलब्धियों का उल्लेख किया, तो कार्यक्रम के बाद बैकस्टेज उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया।



अपनी-सी लगती थीं। दिल्ली के एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक समारोह की वह शाम आज भी मेरी स्मृतियों में ताजा है। उस कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी मुझे मिली थी। उसी मंच पर तीजन बाई का सम्मान होना था और उनके पंडवानी गायन की प्रस्तुति भी। मंच से उनके जीवन परिचय का वाचन करने का अवसर भी मुझे मिला। जब मैंने उनके संघर्ष, साधना और उपलब्धियों का उल्लेख किया, तो कार्यक्रम के बाद बैकस्टेज उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया।

## भाषाओं का लुप्त होना विचारों का लुप्त होना है: प्रो. गणेश देवी

भोपाल। दशकों में संपूर्ण विश्व से 4000 भाषाएं समाप्त हो चुकी हैं और हमारे देश में भी अनेक भाषाएं समाप्ति के कगार पर हैं। इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये विचार पद्मश्री से सम्मानित देश के प्रसिद्ध भाषाविद् प्रो. गणेश देवी ने स्कॉप स्किल ग्लोबल विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा आयोजित समारोह में व्यक्त किए। प्रारंभ में



आईसेक्ट इंडिया समूह के चेअरमैन श्री संतोष चौबे ने शाल अर्पित कर तथा पुस्तकें भेंट कर प्रोफेसर देवी को सम्मानित किया। अंतरराष्ट्रीय हिंदी केंद्र के निदेशक डॉ. जवाहर कर्णावट ने प्रो. देवी को विस्तृत परिचय दिया। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय हिंदी ऑनलाइन 2026 के पोस्टर का लोकार्पण भी अतिथियों ने किया। प्रोफेसर देवी ने भारत की भाषाई विरासत को समझने और 800 लुप्तप्राय भाषाओं को बचाने की दिशा में उनके द्वारा किए गए प्रयासों तथा विश्व के सबसे बड़े भाषाई सर्वे को विस्तार से जानकारी भी दी। अंत में कुलाधिपति सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने आभार प्रदर्शित किया।

## प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने व्यक्त किया शोक

लोककला एवं सांस्कृतिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि तीजन बाई जी का निधन लोककला एवं सांस्कृतिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। अपनी विलक्षण प्रतिभा, कठोर साधना और समर्पण के माध्यम से उन्होंने पंडवानी गायन को देश ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाया। उनका योगदान भारतीय लोक-सांस्कृतिक और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को सदैव समृद्ध करती रहेगा।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके असंख्य प्रशंसकों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दें।

## कृषि मंत्री के ओएसडी समेत तीन कर्मचारी सस्पेंड

बंगले- मंत्रालय में ट्रांसफर के बदले मांगी थी रिश्त

भोपाल (नप्र)। एमपी के कृषि मंत्री एदल सिंह कंधाना के ओएसडी अशोक कुमार बाथम, दिनेश भुकीरिया निज सहायक, स्टेनो टाइपिस्ट अंकित अविधिया को सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तीनों ही ट्रांसफर के एवज में रिश्त की डील कर रहे थे। बता दें कि 1 जून से 16 जून तक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से प्रतिबंध हटाया था। उसी दौरान इन तीनों ने कृषि विस्तार अधिकारी, नर्स और वन रक्षक के ट्रांसफर के एवज में 5 से 15 लाख रुपए की डील की थी।

## सड़क हादसे में घायल महिला की 18 दिन बाद मौत

मायके से लौटते समय कार ने बाइक को मारी थी टक्कर, आरोपी पर बढ़ेगी गंभीर धाराएं

भोपाल (नप्र)। भोपाल के बैरसिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला की 18 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला 19 जून को अपने दो भतीजों के साथ मायके से लौट रही थी, तभी तेज रफ्तार आल्टो कार ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मारी दी थी। बैरसिया पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पहले से दर्ज एफआईआर में अब महिला की मौत के बाद गंभीर धाराएं जोड़ी जाएंगी।

### मायके से लौटते समय हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, 48 वर्षीय शैतान बाई, पत्नी भूर सिंह, नजीबाबाद थाना क्षेत्र के बरसाना गांव की निवासी थीं। वह बैरसिया थाना क्षेत्र स्थित अपने मायके में मेहमानी के लिए आई थीं। 19 जून की शाम वह अपने दो भतीजों के साथ बाइक से घर लौट रही थीं। इसी दौरान चंदा-सलोई मार्ग पर पीछे से तेज रफ्तार आल्टो कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी दी।

### तीनों गंभीर रूप से घायल हुए

हादसे में शैतान बाई और उनके दोनों भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया। शैतान बाई के सिर में गंभीर चोट आई थी और उनका लगातार इलाज चल रहा था।

### इलाज के दौरान तोड़ा दम

करीब 18 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद रविवार सुबह शैतान बाई ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

### आरोपी पर बढ़ेगी धाराएं

बैरसिया पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद आरोपी कार चालक के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका था। अब महिला की मौत के बाद प्रकरण में संबंधित गंभीर धाराएं बढ़ाई जाएंगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।



मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने विधायक रामेश्वर शर्मा के जन्म दिवस पर उन्हें पुष्प-गुच्छ भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं दीं।

# भोपाल में रॉयल एनफील्ड की बाइक रैली

## पुलिस कमिश्नर ने दिखाई हरी झंडी, बाइकर्स ने दिया ट्रैफिक नियमों के पालन का संदेश

भोपाल (नप्र)। भोपाल में रविवार को रॉयल एनफील्ड की ओर से बाइक रैली आयोजित की गई। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने अपने कार्यालय से रैली को हरी झंडी दिखाकर खाना किया।

रैली आईएसबीटी तक निकाली गई, जिसमें देशभर से आए करीब 100 बाइकर्स ने हिस्सा लिया। रैली का उद्देश्य सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति लोगों को जागरूक करना था।

रैली में शामिल बाइकर्स निर्धारित मार्ग से गुजरते हुए आईएसबीटी पहुंचे। इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने सेफ राइडिंग और ट्रैफिक नियमों के पालन का संदेश दिया।

देश के अलग-अलग राज्यों से हिस्सा लेने आए राइडर्स - कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए रॉयल एनफील्ड राइडर्स और बाइकिंग समुदाय के सदस्य शामिल हुए। यह



## कटनी में बड़े उद्योगपति पर जानलेवा हमला

बीजेपी नेता समेत 35 लोगों पर है आरोप, जमीन को लेकर है विवाद

कटनी(नप्र)। मध्यप्रदेश के कटनी जिले में एक उद्योगपति पर दिनदहाड़े जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। पूरा मामला जमीन विवाद को लेकर समाने आया है, जहां करीब आधा सैकड़ बयमशों ने उद्योगपति की कार को घेर लिया और डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित ने भाजपा नेताओं समेत कई लोगों पर मारपीट समेत जान से मारने की प्रयास के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने एफआईआर जांच शुरू कर दी है।

बड़े उद्योगपति पर कर दिया हमला- जानकारी के मुताबिक पूरा मामला कटनी के माधववनगर थाना क्षेत्र स्थित विश्राम बाबा के पास का बताया गया है। जहां जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर पहुंचे जिले के बड़े उद्योगपति मुकेश गुप्ता पर हमला करने लगे। पीड़ित ने आरोप लगाया कि करीब 35 से 40 लोग मौके पर पहुंच गए और कार पर डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान उद्योगपति के साथ भी मारपीट की गई।

35 लोगों पर हमले का आरोप- पीड़ित मुकेश गुप्ता ने भाजपा नेता हर्ष पांडे, रमेश शुक्ला, अरमान द्विवेदी समेत 35 से अधिक लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। घटना के बाद वह सीधे माधववनगर थाना पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है।



### जांच में जुटी पुलिस

वहीं, माधववनगर टीआई संजय दुबे ने बताया कि लिखित शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करते जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है। जमीन विवाद में हुई इस हिंसक वारदात ने शहर की कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि शहर में चटित इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुकेश गुप्ता ने कहा कि मुझे दोपहर में फोन आया कि मेरी जमीन पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। इसके बाद लोगों ने हमला कर दिया। यह जमीन मेरी 20 साल पुरानी है। उस पर बांडू है। इसके बावजूद दूसरे पक्ष के लोग दावा कर रहे हैं।

## 70 हजार टीचर्स को टीईटी से बचाने की कोशिश

एमपी में 2005 से 2009 के बीच भर्ती शिक्षकों के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल (नप्र)। एमपी के करीब 70 हजार टीचरों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से राहत दिलाने स्कूल शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। विभाग का तर्क है कि साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों ने पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नौकरी हासिल की थी, इसलिए उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट यह दलील स्वीकार करता है, तो हजारों शिक्षकों को राहत मिल सकती है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के आदेश के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने अप्रैल में निर्देश जारी कर प्रदेश के स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के उन सभी शिक्षकों के लिए जुलाई-अगस्त में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित कराने को कहा है, जिनकी नियुक्ति साल 1998 से 2009 के बीच, यानी शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून लागू होने से पहले हुई थी।

### 2005 से 2009 में भर्ती शिक्षकों को राहत दिलाने की तैयारी

स्कूल शिक्षा विभाग साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए करीब 70 हजार शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से राहत दिलाने के लिए नया कानूनी प्रयास कर रहा है। इन शिक्षकों की नियुक्ति सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के आधार पर हुई थी। हालांकि, यह परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) नहीं थी और न ही इसे नेशनल कार्डिसल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित किया गया था। सूत्रों के मुताबिक, विधि विभाग और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से राय लेने के बाद राज्य सरकार एक सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर कर सकती है। याचिका में अदालत से अनुरोध किया जाएगा कि साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती शिक्षकों ने पहले ही सरकारी चयन परीक्षा पास कर नियुक्ति प्राप्त की है, इसलिए उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने से छूट दी जाए। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि इस याचिका में राहत मिलने की संभावना सीमित है, लेकिन शिक्षकों के हित को देखते हुए यह कानूनी पहल की जा रही है। यदि सुप्रीम कोर्ट राहत देता है, तो पात्रता परीक्षा के दायरे में आने वाले करीब आधे शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकता है। फिलहाल मामला विचारार्थीन होने के कारण विभाग के अधिकारी आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं।

इस आदेश से प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच साल से कम है, उन्हें परीक्षा से छूट मिलेगी। वहीं, पांच साल से अधिक सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना जरूरी होगा। परीक्षा पास नहीं करने वाले टीचरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने टीईटी पास करने की समयसीमा पहले 31 अगस्त 2027 तक की थी। जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी गई है।

व्यापम के माध्यम से इन वर्षों में हुई शिक्षक भर्ती- स्कूल शिक्षा विभाग ने साल 2005-06 में पहली बार व्यापम (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इसके बाद 2008-09 में भी व्यापम के जरिए भर्ती परीक्षा कराकर शिक्षकों की नियुक्तियां की गईं। वहीं 2010-11 और 2012-13 में गुरुजी और अनुदेशकों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गईं।

### दोबारा याचिका पर भी नहीं मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने पात्रता परीक्षा कराने के निर्देश जारी किए तो शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया। इसके बाद विभाग और शिक्षक संगठनों ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर आदेश में राहत की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया कि पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य होगा और इस शर्त में कोई छूट नहीं दी जा सकती। हालांकि, कोर्ट ने शिक्षकों को आशिक राहत देते हुए परीक्षा आयोजित करने की समय-सीमा एक साल बढ़ाकर अगस्त 2028 तक कर दी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जो शिक्षक पहली बार में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, उन्हें बाद में होने वाली प्रत्येक पात्रता परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। ऐसे में अब स्कूल शिक्षा विभाग के पास निर्धारित समय-सीमा के भीतर पात्रता परीक्षा आयोजित कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

### 65 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर चुका है सुप्रीम कोर्ट

शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट 65 से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर चुका है। ये याचिकाएं राज्य सरकारों, शिक्षक संगठनों और व्यक्तिगत शिक्षकों ने दायर की थीं। सभी ने 2025 के फेसले पर पुनर्विचार मांगा था।

# साइकिल से सीहोर पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी

भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरा, 14-15 जुलाई से नए अभियान का ऐलान

सीहोर (नप्र)। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी रविवार सुबह करीब 9.50 बजे साइकिल चलाते हुए सीहोर पहुंचे। उन्होंने जन-जन से जुड़ने और जनता की आवाज बुलंद करने के उद्देश्य से यह यात्रा शुरू की। सीहोर पहुंचने पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती और शहर कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

सीहोर पहुंचने के बाद पटवारी ने प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर मध्य प्रदेश की खुशहाली और जनता की समृद्धि की कामना की।



गणेश मंदिर से निकलने के बाद जीतू पटवारी ने प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में अद्भुत और अकल्पनीय भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और यह सरकार अलीबाबा चालीस चोर की तरह काम कर रही है। अयोध्या चढ़ावा केस को खुला भ्रष्टाचार बताया- पटवारी ने अयोध्या के जमीन घोटालों

और महाकाल लोक में कथित लूट का जिक्र करते हुए कहा कि इन गंभीर सवालों पर मुख्यमंत्री पूरी तरह मौन हैं। उन्होंने अयोध्या में चढ़ावा चोरी की घटना को खुला भ्रष्टाचार करार दिया।

इस दौरान जीतू पटवारी ने कांग्रेस के भविष्य के विजन और राहुल गांधी की सोच पर आधारित एक बड़े अभियान की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 14 और 15 तारीख को कांग्रेस नई सोच और क्रांतिकारी विचार के साथ पूरे मध्य प्रदेश में जनता के बीच जाएगी इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के हर बच्चे के लिए सुरक्षित शिक्षा और शिक्षा की गारंटी सुनिश्चित करना है।

### कहा- दतिया में बीजेपी के खिलाफ भारी आक्रोश

पटवारी ने अपने दतिया दौर के अनुभव साझा करते हुए कहा कि वहां की जनता में भाजपा शासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। उन्होंने दावा किया कि लोग अब बदलाव के लिए तैयार हैं और आगामी चुनाव में दतिया से कांग्रेस शत-प्रतिशत ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। जीतू पटवारी की इस साइकिल यात्रा और जन-सरोकार के मुद्दों ने सीहोर सहित पूरे प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है।

## संपादकीय

## हम फुटबॉल में फिसड़ी क्यों

इन दिनों पूरी दुनिया पर विश्व कप फुटबॉल का जुनून छाया हुआ है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में हो रहे इन मैचों को देखने के लिए भारत में भी लोग रात-रात भर जाग रहे हैं। हर मैच का अलग रोमांच है। विश्व कप की दवेदार कई बड़ी टीमों राउंड 16 तक आते-आते टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। फुटबॉल खिलाड़ी एक गोल करने और बचाने के लिए जी जान लगा रहे हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाले देश भारत को इस विश्व कप फुटबॉल में उपस्थिति कहीं नहीं है, जब कप वर्द और हैती जैसे देश भी अपनी दमदार टीमों के साथ विश्व कप में मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। यह सवाल फिर से मौजू है कि क्रिकेट का दीवाना भारत फुटबॉल में इतना फिसड़ी क्यों है? भारत ही क्यों चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे बड़ी आबादी वाले देश में भी फुटबॉल में बहुत पीछे हैं। हालांकि फुटबॉल इन देशों में बहुत लोकप्रिय है, बावजूद इसके इनकी फुटबॉल टीमों और फुटबॉल खेल प्रबंधन बहुत निचले स्तर पर और कमजोर है। अगर आबादी को ही मानक मान लिया जाए तो बड़ी आबादी वाले सिर्फ दो देश यानी अमेरिका और ब्राजील ही वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई कर सके हैं। जबकि दो अन्य बड़ी आबादी वाले देश रूस और नाइजीरिया पिछले कई विश्व कप में खेल चुके हैं। चीन और इंडोनेशिया वर्ल्ड कप फुटबॉल में केवल एक-एक बार ही हिस्सा ले पाए हैं। जबकि दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत के साथ-साथ बांग्लादेश, इथियोपिया और पाकिस्तान अब तक केवल विश्व कप में खेलने का सपना ही देख पाए हैं। हालांकि भारत ने तकनीकी रूप से 1950 में ब्राजील में हुए विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से एक घंटे से भी कम समय पहले उसने अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि किसी देश को आबादी और उसकी फुटबॉल टीम के ताकतवर होने न होने का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। अत्यंत गरीब महाद्वीप अफ्रीका के कई देशों की टीमों भी दम दिखा रही हैं। और अखेट फुटबॉल खिलाड़ी तो लगभग सभी देशों की टीमों में हैं। हालांकि, ब्रिटिश शिक्षाविद्, अर्थशास्त्री तथा चर्चित किताब 'संकरनामिकस' के सह-लेखक स्टीफन शिमांस्की कहते हैं कि आबादी कई महत्वपूर्ण कारकों में से केवल एक है। फुटबॉल काफी हद तक किसी देश की अर्थव्यवस्था की तरह काम करता है। तरक्की के लिए लोगों की जरूरत होती है, लेकिन इसके साथ पूंजी और बुनियादी ढांचे की भी उतनी ही जरूरत होती है। फुटबॉल में इसका मतलब है बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने और उन्हें आगे बढ़ाने की क्षमता। शिमांस्की और उनके सह-लेखक साइमन कूपर ने प्रायः कि किसी देश को बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिताओं जीतने के लिए आमतौर पर प्रति व्यक्ति औसत सालाना आय कम से कम 15 हजार अमेरिकी डॉलर होनी चाहिए। लेकिन ब्राजील और अर्जेंटीना, जहां प्रति व्यक्ति औसत आय इस स्तर से काफी कम है, दोनों मिलकर अब तक आठ बार विश्व कप जीत चुके हैं। ब्रिटिश अर्थशास्त्री के मुताबिक, यह तीसरे महत्वपूर्ण कारक की अहमियत को दिखाता है, और वह है 'खेल के बारे में जानकारी। यह अनुभव के साथ आता है। जिन देशों ने कभी विश्व कप जीता है, वे वही देश हैं जो क़रीब सौ साल पहले यानी उन्विशेवादी का दौर खत्म होने से पहले फुटबॉल में सबसे आगे थे। भारत के पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर श्याम थापा का मानना है कि आईपीएल की सफलता के कारण मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग के माता-पिता अपने बच्चों को फुटबॉल के बजाय क्रिकेट की ओर ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं।

## नजरिया

## रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।



पिछले दिनों मुरैना में पत्थर खदानों से रेत खनन के समाचार प्रमुखता से समाचार पत्रों में आये। खनन माफिया का हौसला इतना बढ़ा है कि उन्होंने अनेक अधिकारियों के वाहन रोकने का प्रयास किया, उनके ऊपर ट्रेक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। कई कर्मचारी वन और राजस्व विभाग के घायल हुए और कुछ तो शहीद हो गये। कई अखबारों ने खनन वालों के बयान छपे कि वे पुलिस थाने के सामने से निकलते हैं, परंतु उन्हें रोकने की हिम्मत पुलिस में नहीं है। क्योंकि खनन करने वाले बंदूक रखते हैं और कर्मचारी भी जानते हैं कि वह गोली भी मार सकते हैं। मुरैना के राज्य सरकार के एक मंत्री ने बयान दिया है कि खनन करने वाले नौजवानों की लाचारी है क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। इस पक्ष से इंकार नहीं किया जा सकता कि बेरोजगारी भी एक कारण है परंतु यह भी तथ्य है कि अब बेरोजगार नौजवान तो खनन करने वाले हैं या ट्रेक्टर आदि चलाने वाले हैं, याने एक प्रकार के अल्प वेतन भोगी श्रमिक जैसे हैं। इनके मालिक बड़े माफिया हैं जो इन नौजवानों से यह कार्य कराते और वे बेरोजगार नहीं हैं। बल्कि वह करोड़पति हैं जिनके पास बड़े-बड़े मकान हैं, गाड़ियां हैं और अपराध करने वाले उनके कर्मचारी हैं। वैसे तो यह खनन का सिलसिला कोई आज का नहीं है बल्कि इसकी शुरुआत तो 1971 के बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उनके बेटे स्वरु संजय गांधी सत्ता के अधोषित नियंत्रक थे, तभी हो चुकी थी। दिल्ली के आसपास के 30-40 किमी के दायरे के पहाड़ों को खोदने वाले उस समय सभी कांग्रेस समर्थक थे। स्व. संजय गांधी के लठैत थे और आज वे भी दिल्ली के पाश इलाकों में बड़े-बड़े मकान बनाकर रह रहे हैं और कारों में चल रहे हैं।

सत्ता के संरक्षण में वह छोटी हो या बड़ी हो खनन माफिया पनवते हैं। और इसी प्रकार रेत का खनन भी देश के अधिकांश इलाकों में बड़ी मझौली या छोटी नदियों के पास रेत का खनन कराने वाले रेत माफिया और आमतौर पर माफिया सरपना उस स्थानीय जाति, जिसकी संख्या व बाहुबल होता है, के होते हैं। खनन करने वाले उनके कर्मचारी होते हैं। खनन से देश के पर्यावरण पर जो असर पड़ा है इसका कोई विधिवत आकलन अभी तक नहीं हुआ है। न सरकारों ने कराया है और न किसी अन्य प्रकृति के संरक्षकों ने

## खनन माफिया और सरकार

मुरैना के राज्य सरकार के एक मंत्री ने बयान दिया है कि खनन करने वाले नौजवानों की लाचारी है क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। इस पक्ष से इंकार नहीं किया जा सकता कि बेरोजगारी भी एक कारण है परंतु यह भी तथ्य है कि अब बेरोजगार नौजवान तो खनन करने वाले हैं या ट्रेक्टर आदि चलाने वाले हैं, याने एक प्रकार के अल्प वेतन भोगी श्रमिक जैसे हैं। इनके मालिक बड़े माफिया हैं जो इन नौजवानों से यह कार्य कराते और वे बेरोजगार नहीं हैं। बल्कि वह करोड़पति हैं जिनके पास बड़े-बड़े मकान हैं, गाड़ियां हैं और अपराध करने वाले उनके कर्मचारी हैं। वैसे तो यह खनन का सिलसिला कोई आज का नहीं है बल्कि इसकी शुरुआत तो 1971 के बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उनके बेटे स्वरु संजय गांधी सत्ता के अधोषित नियंत्रक थे, तभी हो चुकी थी।

कराया है। सरकारों से तो उम्मीद करना ही व्यर्थ है क्योंकि आमतौर पर यह सभी खनन माफिया सरकारों के संरक्षण में ही चलते हैं। सत्ता के मुखिया की जाति के नाम उनके ट्रेक्टरों और वाहनों पर लिखे रहते हैं, उनसे दुर्घटनायें होती हैं, निर्दोष लोग मरते हैं, परंतु सरकार के मुखिया के संरक्षण के चलते प्रशासन व पुलिस उन्हें रोकना, पकड़ना या अपराध दर्ज करना तो दूर उन्हें दूर से सलाम करते हैं। पत्थर और रेत के खनन से कितने ही इलाकों में खदानें बन गई हैं और इन खदानों में पानी भरने से अनजाने में लोग डूबकर मर जाते हैं क्योंकि उन्हें इनका कोई अनुमान नहीं होता। इन सामान्य व निर्दोष लोगों को सरकारें भी कोई मुआवजा नहीं देती क्योंकि वे दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में रहने वाले होते हैं। लगातार नदियों से रेत निकालने से जो नदियों के जल का शुद्धिकरण होता था वह घट रहा है और नदियां मिट्टी के दलदल में बदल रही हैं। पत्थरों को खोदने के लिये वनों को काटा जाता है और वनों की संख्या इस कारण से घट रही है परंतु आज तक देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मन की बात में पर्यावरण नष्ट करने वाले, प्रकृति को नष्ट करने वाले इन खनन माफियाओं के बारे में कोई चिंता व्यक्त नहीं की? हो सकता है कि उसका एक कारण यह भी हो कि इन दिनों देश के लगभग 22 राज्यों में भ्रजणा या एनडीए की सरकारें हैं जो उनकी अपनी है और अपनी सरकारों के अपराधों के बारे में बोलना उनकी संस्कृति नहीं है बल्कि अपनों के अपराध पर पर्दा डालना और दूसरों के अपराध को बढ़ा चढ़ा कर बताना उनकी शैली है या राजनैतिक चतुराई है। अगर यह खनन नहीं रुका तो कुछ वर्षों के बाद देश की बड़ी व पवित्र मानी जाने वाली नदियां भी मिट्टी के

दलदल में बदल जायेंगी, वही बड़े-बड़े पहाड़ भी पत्थरों के टिले बन जायेंगे। आज सरकार के वन मंत्री की छत्रछाया में भारत सरकार ने तो अरावली पर्वत में खनन की अनुमति को लेकर जो योजना प्रस्तुत की थी, उसमें तो यह कह दिया गया था कि अगर 200 मी. के ऊपर पहाड़ है, तो वही पहाड़ माना जायेगा तथा उसमें खनन की अनुमति दी जा सकेगी। भारत सरकार के इस प्रस्ताव पर पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने बगैर



अध्ययन व विचार कर स्वीकृति की मुहर लगा दी, पर सारे राजस्थान व देश से जब अरावली बचाओ का अभियान शुरू हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दोषी बताते हुए अपना आदेश वापिस लिया। यह सर्वविदित है कि अरावली पर्वत में बड़ी संख्या में बड़ी पर्वत श्रृंखलायें हैं और यह सभी पर्वतों में होती है। अगर एक बार यह पर्वत श्रृंखलायें कट कर साफ हो जाती, चट्टान व पर्वतों को खोद दिया जाता तो राजस्थान का क्या होता? प्राण वायु कहां से मिलती? वर्षा के लिये बादल कहां से रुकते, कितना सूखा पड़ता इन सबके बारे में सरकारों को कोई चिंता नहीं। आज धारणा यह बन चुकी है कि सरकारों व प्रशासन तंत्र को केवल रिश्त कर्त चिह्न चाहिए चाहे देश का कुछ भी हो। यह पर्वत श्रृंखला मात्र पर्यावरण की संरक्षक नहीं हैं

## चढ़वा चोरी: क्या इस मामले में हो रही कार्रवाई पर्याप्त है?

स्थानीय कोतवाली में पहले से कई लिखित शिकायतें (तहरीर) उपलब्ध थीं। फिर प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब क्यों हुआ? यदि एसआईटी केवल वही तथ्य संकलित कर रही थी, जिनके आधार पर बाद में मात्र गिनती में हुई गड़बड़ियों के लिए एफआईआर दर्ज हुई, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या यह प्रक्रिया आवश्यक थी अथवा इससे कार्रवाई टलती रही? 'देर आए दुरुस्त आए' या फिर 'दाल में कुछ काला है'—यह निर्णय अंततः जांच के निष्कर्ष ही करेंगे। एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, किंतु उसकी अंतरिम रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। पारदर्शिता की दृष्टि से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि जनता को कम-से-कम इतना अवश्य बताया जाए कि जांच की दिशा क्या है और किन बिंदुओं पर आगे कार्रवाई प्रस्तावित है। दूसरी ओर, कथित भूमि लेन-देन संबंधी आरोपों पर अब तक न तो कोई अलग प्राथमिकी दर्ज हुई है और न ही उस संबंध में एसआईटी ने जांच की ?

भी एक अभियुक्त के बयान के आधार पर बिना किसी प्राथमिकी जांच के एफआईआर दर्ज हो जाती है। अंततः न्यायालय अपराध का कोई प्रथम दृष्टया सबूत न मिलने पर केजरीवाल को आरोपों से मुक्त (डिस्चार्ज) कर देता है। इसी प्रकार अनेक चर्चित मामलों में प्रारंभिक उपलब्ध सामग्री के आधार पर पहले एफआईआर दर्ज हुई और बाद में जांच आगे बढ़ी।

इसके विपरीत, श्रीराम मंदिर प्रकरण में कथित अनियमितताओं की चर्चा, शिकायतें, जांच और कथित बरामदगी जैसी बातें सामने आने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज होने में समय लगा। ट्रस्ट व मंदिर से जुड़े व्यक्तियों की 'असामान्य समर्पित' होने के मामले में भी गबन के पैसे का दुरुपयोग कुछ हुआ है, के लिए इंडी, आयकर विभाग की जांच तक अभी प्रारंभ नहीं हुई है। यदि यही तथ्य हैं, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि इस मामले में प्रक्रिया अलग क्यों रही? कानून की विश्वसनीयता तभी बनती है, जब न्याय केवल 'निष्पक्ष हो ही नहीं, बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी दे'।

राम मंदिर निर्माण से जुड़े आर्थिक प्रश्न पहली बार नहीं उठे हैं। 2015-2017 में निर्माही अखाड़ा और

अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने विश्व हिंदू परिषद पर राम मंदिर निर्माण के नाम पर जमा 1400 करोड़ रुपये की हेराफेरी के आरोप लगाये थे। वर्तमान में चर्चा तब प्रारंभ



हुई, जब पूर्व मंत्री पवन पांडे की शिकायत से अखिलेश ने इस मुद्दे को लपका। वर्तमान विवाद तब अधिक चर्चा में आया जब इस विषय को राजनीतिक स्तर पर अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री पवन पांडेय द्वारा एक दिन पूर्व की गई शिकायत के आधार पर उठया इसके बाद ही प्रशासनिक कार्रवाई प्रारंभ हुई। ऐसे में प्रश्न केवल एक

मंदिर या एक ट्रस्ट का नहीं है, बल्कि उन करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का है, जिन्होंने अपनी श्रद्धा, भक्ति, आस्था से दान दिया है।

निष्पक्ष जांच के लिए नैतिक उत्तरदायित्व। श्रीराम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की 'आस्था' का केंद्र है। इसलिए यहाँ पारदर्शिता का मानक सामान्य संस्थाओं से भी अधिक होना चाहिए। जांच की समस्त गड़बड़ियाँ तार्किक और निर्विवाद निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए यह आवश्यक है कि इसकी निगरानी किसी स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था अथवा सक्षम न्यायिक पर्यवेक्षण में हो। इससे जांच की विश्वसनीयता और जन विश्वास दोनों सुदृढ़ होंगे।

ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय द्वारा बरती गई 'सावधानी और सुरक्षा काबिले तारीफ है? विश्व सिंधी सेवा समामग के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजू मनवानी का कथन कि चंपत राय ने उनके द्वारा दी गई 200 चांदी की ईंटें की रसीद तुरंत न देकर चांदी की शुद्धता की जांच के बाद देने का कथन किया, जो आज तक बार-बार मांगने के बावजूद नहीं मिली।

अनीता भारद्वाज ने भी चांदी का 'कागधुशुण्ड' की मूर्ति देने व रसीद न मिलने का सार्वजनिक बयान दिया है। आपके-हमारे द्वारा मंदिर में चढ़ावा देते समय न तो (नकली) नोटों की जांच होती है, न दिये गये सामग्री की जांच होती है। न ही मंदिर प्रशासक दान की वस्तु को वापिस करता है। अंबानी और बड़े-बड़े अभिनेता मंदिर में सोने-चांदी के दान देते हैं। क्या उनकी भी इस तरह की जांच की गई थी? उत्तर गर्भ में है? लेकिन जब एक व्यक्ति चंपत राय इतनी सतर्कता बरत रहे हैं, तब जांच में पारदर्शिता लाने के लिए क्या यह आवश्यक है कि समस्त आरोपियों को उनके पदों से हटा दिया जाए? यदि वे इस्तीफा नहीं देते तो। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पर कोई आरोप सिधे नहीं लगता है लेकिन कोषाध्यक्ष होने के नाते समस्त वैधानिक व नैतिक प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। 'सीज़र की पत्नी संदेह से भी परे होनी चाहिए' - यह सिद्धांत सार्वजनिक जीवन में आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आस्था की संस्थाओं के लिए तो यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है।

आस्था सर्वोपरि, पारदर्शिता अनिवार्य भगवान श्रीराम करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। इसलिए इस प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि श्रद्धालुओं का विश्वास किसी भी स्थिति में कमजोर भंग नहीं होना चाहिए।

कहा भी गया है—

'होइहि सोइ जो राम रचि राखा।'

लेकिन मनुष्य का कर्तव्य भी उतना ही स्पष्ट है कि वह सत्य, ईमानदारी और पारदर्शिता का पालन करे। आस्था का संरक्षण केवल मंदिर निर्माण से नहीं, बल्कि उसके प्रबंधन की निष्कलंक पारदर्शिता से भी होता है। 'दूध का दूध और पानी का पानी' होना ही इस मामले की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि ऐसा होता है, तभी भगवान श्री राम के नाम पर दिए गए प्रत्येक अंशदान का सम्मान भी सुरक्षित रहेगा और जनता का विश्वास भी अक्षुण्ण बना रहेगा।



## राजीव खडेलवाला

(लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष, बैतूल सुधार न्यास)

अंततः श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की लिखित तहरीर पर मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के संबंध में प्राथमिकी दर्ज हुई, आठ छुटपेये 'छोटी मझौलियों' की गिरफ्तारी हुई, एसआईटी का गठन हुआ और बाद में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय तथा ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा ने नैतिक आधार पर अपने इस्तीफे सौंप दिए। यह घटनाक्रम देर से ही सही, लेकिन आगे बढ़ा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह कार्रवाई पर्याप्त है अथवा अभी भी जांच की दिशा और दायरा अधूरा है?

स्थानीय कोतवाली में पहले से कई लिखित शिकायतें (तहरीर) उपलब्ध थीं। फिर प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब क्यों हुआ? यदि एसआईटी केवल वही तथ्य संकलित कर रही थी, जिनके आधार पर बाद में मात्र गिनती में हुई गड़बड़ियों के लिए एफआईआर दर्ज हुई, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या यह प्रक्रिया आवश्यक थी अथवा इससे कार्रवाई टलती रही? 'देर आए दुरुस्त आए' या फिर 'दाल में कुछ काला है'— यह निर्णय अंततः जांच के निष्कर्ष ही करेंगे।

एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, किंतु उसकी अंतरिम रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। पारदर्शिता की दृष्टि से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि जनता को कम-से-कम इतना अवश्य बताया जाए कि जांच की दिशा क्या है और किन बिंदुओं पर आगे कार्रवाई प्रस्तावित है। दूसरी ओर, कथित भूमि लेन-देन संबंधी आरोपों पर अब तक न तो कोई अलग प्राथमिकी दर्ज हुई है और न ही उस संबंध में एसआईटी ने जांच की ?

कानून की निष्पक्षता का आकलन प्रायः तुलनात्मक दृष्टि से किया जाता है।

लखनऊ के भीषण अग्निकांड में घटना के तुरंत बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और उसके बाद विस्तृत जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। केजरीवाल मामले में

## खंग्व

## राजेंद्र बज

लेखक खंग्वकार हैं।



फिर भी समय राजकुमार सिद्धार्थ आध्यात्मिक दृष्टि से सत्य की खोज हेतु सांसारिक मोह माया और बंधनों को दरकिनार करते हुए अपने राजमहल का त्याग कर गए थे। लेकिन मैं तो इस संसार में रहकर विशुद्ध रूप से सांसारिक हूं। यही कारण है कि मीडिया जगत में तमाम तरह के आरोप-प्रत्यारोप और खंडन-मुंडन के बीच मुझे भी इन संदर्भों में सत्य की तलाश है। क्या तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और क्या तो सोशल मीडिया, हर कोई मुझे घनचक्कर कर देता है। एक बात पर जरा भी विश्वास होने लगता है कि इसके तुरंत बाद उस बात पर घात लगाते हुए दूसरी-तीसरी और चौथी-पांचवीं बात मीडिया जगत में छ़ा जाया करती है। दरअसल सत्य के प्रति मेरा गहरा समर्पण रहा

## आरोप-प्रत्यारोप और खंडन-मुंडन के बीच सत्य की तलाश

है, इसलिए इनके कहे और उनके कहे में अंतर्निहित परम सत्य जब तक न जान लूँ, दिल और दिमाग को रती भर भी सुकून नहीं मिलता। मीडिया में आए दिन नए-नए गुल खिलते रहा करते हैं। जिसे शाब्दिक 'ठोकाठाकी' के रूप में भी जाना जा सकता है। हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग केवल और केवल राजनीतिक एवं सामाजिक बिरादरी में होता आया है। जिसमें कुछ तत्व ठहरे हुए पानी में कंकर फेंक कर लहरों को गिनने का लुप्त उठाते हैं। इस बिरादरी में एक से बढ़कर एक बोलकर है जो आए दिन कुछ न कुछ बोल कर जमाने को अपने अस्तित्व का एहसास कराते रहे हैं। कभी-कभी आक्रोश या भावनाओं के अतिरेक में कुछ अनर्गल शब्दावली का उपयोग करने में भी आ जाते तो बहुत आसानी के साथ यू टर्न लिया जा सकता है। वैसे जहर उगलकर भी 'मेरा यह आशय नहीं था' का उद्धोष करते हुए बचाव की मुद्रा में भी

आया जा सकता है। या फिर खेद व्यक्त करते हुए अपने शब्द वापस लिए जा सकते हैं। और हाँ, अपने बोलवचन के लिए क्षमा मांगने के बाद तो सारी की सारी बात ही आई-गई मान ली जाती है। अब यह अलग बात है कि तीर तो अपना निशाना साध चुका होता है। वैसे मीडिया में कोई बात उछल जाने पर आम नागरिकों की सामान्य जानकारी में बहुत इजाफा हुआ करता है।

लेकिन समस्या तो तब आती है जब तमाम तरह की खबरों के बीच कोई शरिखसत उसके परम सत्य को जानने के प्रति आतुर होता है। यह अलग बात है कि कुछ लोग मीडिया के तीनों अंगों को फौरी तौर पर लिया करते हैं। जिसके चलते तमाम तरह की सनसनीखेज और हैरतअंगेज खबरों के चलते भी उनके दिल और दिमाग पर अतिरिक्त बोझ नहीं आता। वैसे इस वर्ग के लोग निरंतर बढ़ती महंगाई और फलते फूलते भ्रष्टाचार से इस कदर विचलित रहा

करते हैं कि उद्धेलित कर देने वाली खबरें भी उन्हें विचलित नहीं कर पाती। यही कारण है कि आए दिन होने वाले मीडिया में उबाल के बावजूद हर आदमी उद्धेलित नहीं होता।

दरअसल खया-पिया आदमी डकार लेने में ही इस कदर व्यस्त होता है कि राजनीतिक और सामाजिक परिवेश की उथल-पुथल से कतई कोई वास्ता ही नहीं रखता। अब हमारे यहाँ अधिकांश आबादी तो मुफ्त राशन पर निर्भर है जिसके चलते जमाने में जो कुछ होता हो, वह हो, अपना तो पेट पल रहा है, यह सोचकर तान खूँटी सोया ही करती है। कामकाजी लोग अपने कामकाज में व्यस्त रहा करते हैं। इसलिए उनके पास अतिरिक्त समय कहां? तमाम तरह के राजनीतिक तथा सामाजिक जगत के आरोप प्रत्यारोप और खंडन मंडन के परम सत्य की तलाश उन्हीं को रहा करती है जो अपने अपने अपने परिवार से इतर राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर भी नजर इनायत करता है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-वी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ज़ोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक उमेश त्रिवेदी  
कार्यकारी प्रधान संपादक अजय बोकिल  
संपादक (मध्यप्रदेश) विनोद तिवारी  
वरिष्ठ संपादक पंकज शुक्ला  
प्रबंध संपादक अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)  
RNI No. MP/HIN/ 2003/ 10923,  
Ph. No. 0755-2422692, 4059111  
Email- subahsaverere.news@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सम्बन्ध नहीं है।

## न्याय और कानून

समान नागरिक संहिता-1

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलीसीटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)



राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड, 2026' का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए हाल ही में एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) इस कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी होंगे। प्रस्तावित कानून के फ्रेमवर्क में शादी, तलाक, बहुविवाह पर रोक, लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, पैतृक संपत्ति में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार आदि से जुड़े प्रावधान शामिल होंगे। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि कमेटी जनता से राय-मशविरा करेगी और एक खास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों की राय और सुझाव भी इकट्ठा करेगी।

समान नागरिक संहिता भारत के विधिक एवं सामाजिक परिदृश्य में एक लंबे समय से लंबित और जटिल मुद्दा बना रहा है। इस कानून का उद्देश्य वर्तमान प्रणाली को बदलना है, जहाँ विभिन्न धार्मिक समुदाय विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मामलों में अपने स्वयं के व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं। समर्थकों का तर्क है कि यह कानून राष्ट्रीय एकीकरण, लैंगिक न्याय और विधि के समक्ष समता को बढ़ावा देगा। आलोचक चिंता जताते हैं कि यह धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण को क्षति पहुंचा सकता है। समान नागरिक संहिता की अवधारणा स्वतंत्रता के बाद से ही भारत के संवैधानिक ढांचे का अंग रही है। इसे राज्य के नीति के निदेशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। हालांकि, इसका कार्यान्वयन दशकों से बहस और विवाद का विषय रहा है। समान नागरिक संहिता के इर्द-गिर्द होने वाली चर्चा धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार और समान नागरिक विधिक एवं भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संतुलन जैसे संवेदनशील मुद्दों का स्पर्श करती है।

समान नागरिक संहिता भारत के सभी नागरिकों के लिये विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, विरासत एवं उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाली विधियों के एक समूह को संदर्भित करती है। इसकी

# इस कानून का उद्देश्य वर्तमान प्रणाली को बदलना

'समान नागरिक संहिता' की अवधारणा स्वतंत्रता के बाद से ही भारत के संवैधानिक ढांचे का अंग रही है। इसे राज्य के नीति के निदेशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। हालांकि, इसका कार्यान्वयन दशकों से बहस और विवाद का विषय रहा है। समान नागरिक संहिता के इर्द-गिर्द होने वाली चर्चा धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार और समान नागरिक विधिक एवं भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संतुलन जैसे संवेदनशील मुद्दों का स्पर्श करती है।

अवधारणा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य नीति के निदेशक तत्व के रूप में किया गया है, जहाँ कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, कि यह कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य के लिये एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। समान नागरिक संहिता का इतिहास भी रोचक है। मूल अधिकारों पर उप-समिति संविधान के लिए मूल अधिकारों का मसौदा तैयार करने के क्रम में उप-समिति सदस्यों (बीआर अंबेडकर, केएम मुंशी और मीनू मसानी) ने समान नागरिक संहिता को अपने मसौदे में शामिल किया था। अधिकारों का विभाजन उप-समिति ने मूल अधिकारों को वाद-योग्य और वाद-अयोग्य श्रेणियों में विभाजित किया। इसको वाद-अयोग्य श्रेणी में रखा गया। मीनू मसानी, हंसा मेहता और अमृत कौर ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि धर्म पर आधारित व्यक्तिगत कानून राष्ट्रीय एकता में बाधा डाल सकते हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता को वाद-योग्य अधिकार के रूप में पेश करने की वकालत की।

अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 35 के मसौदे (जो बाद में अनुच्छेद 44 बना) ने समान नागरिक संहिता को निदेशक तत्वों में शामिल किया, जिससे यह गैर-अधिदेशात्मक हो गया। इस्माइल साहब और पोकल साहब बहादुर जैसे मुस्लिम नेताओं ने तर्क दिया कि समान नागरिक संहिता धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है और इससे असामंजस पैदा होगा। केएम मुंशी ने राष्ट्रीय एकता

और धर्मनिरपेक्षता के लिए समान नागरिक संहिता की वकालत की, जहाँ हिंदू समुदायों की चिंताओं पर भी ध्यान दिया। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने तर्क दिया कि समान नागरिक संहिता से सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा और सवाल उठेगा कि मौजूदा समान दंड संहिता के विरुद्ध कोई विरोध क्यों नहीं हुआ। भीमराव अंबेडकर समान नागरिक संहिता

की वैकल्पिक प्रकृति पर बल दिया और इसे नीति निदेशक तत्वों में शामिल करने को समझौता बतलाया। यूसीसी पर न्यायालयों के न्याय निर्णयों में भी कुछ न्यायिक घोषणाएँ की गईं। शाहबानो प्रकरण (1985) में न्यायालय ने एक मुस्लिम महिला के भरण-पोषण के अधिकार की पुष्टि की और समान नागरिक संहिता को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़कर देखा। जॉर्डन डिग्रेडेड प्रकरण में तलाक कानूनों की विसंगतियों को उजागर किया गया और विधिक एकरूपता के लिये यूसीसी की मांग की

गई। सरला मुद्गल प्रकरण में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का प्रबल समर्थन किया गया, विशेष रूप से बहुसंख्यक हिंदू आबादी के लिए और इसके कार्यान्वयन में हो रही देरी पर सवाल उठाया। पन्नालाल बंसीलाल पिट्टी प्रकरण में भारत की बहुलवादिता को स्वीकार किया गया तथा समान नागरिक संहिता के क्रमिक कार्यान्वयन का तर्क दिया गया। लिली थॉमस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराधिकार के संदर्भ में यूजीसी के महत्व पर बल दिया। जॉन वल्लभमट्टम प्रकरण में ईसाई पर्सनल लॉ में मौजूद भेदभावपूर्ण प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया और समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया गया। शबनम हाशमी प्रकरण में किशोर न्याय अधिनियम को यूसीसी से जोड़ा गया और धर्मनिरपेक्ष कानूनों की आवश्यकता पर बल दिया। शायरा बानो प्रकरण (2017) में तीन तलाक के मुद्दे पर विचार किया गया, लेकिन समान नागरिक संहिता को मानवाधिकारों के मुद्दे से अलग कर देखा गया।

समान नागरिक संहिता के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, उनमें विधि के अंतर्गत समता धार्मिक बाधाओं को तोड़ना। समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिये समान अधिकार और व्यवहार सुनिश्चित करेगी, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। साथ ही यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के अनुरूप है, जो विधि के समक्ष समता

की गारंटी देता है। यह भी कहा जाता है कि समान नागरिक संहिता विवाह कानूनों को मानकीकृत करेगी तथा लैंगिक समानता एवं धार्मिक तटस्थता को बढ़ावा देगी। उत्तराखंड में हाल ही में समान नागरिक संहिता के द्वारा बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सभी के लिये विवाह की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई। कई व्यक्तिगत कानूनों की महिलाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण होने के लिए आलोचना की जाती है। समान नागरिक संहिता तीन तलाक, असमान उत्तराधिकार अधिकार और बाल विवाह जैसे मुद्दों का समाधान कर सकती है। विभिन्न सर्वे से यह ज्ञात होता है कि 20-24 आयु वर्ग की 23.3% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गया था, यह समान विवाह कानूनों की आवश्यकता को उजागर करता है।

यह भी कहा जाता है कि यह कानूनी प्रणाली को सरल बनाय व्यक्तिगत कानूनों को सुव्यवस्थित करना भी है। भारत में धर्म के आधार पर कई व्यक्तिगत कानूनों की वर्तमान प्रणाली एक जटिल कानूनी परिदृश्य का निर्माण करती है। आशा है समान नागरिक संहिता इस प्रणाली को सरल बनाएगी। इससे न्यायालयों के लिए न्याय करना आसान हो जाएगा। साथ ही नागरिकों के लिए भी अपने अधिकारों को समझना सरल हो जाएगा। सिविल मामलों में पर्सनल लॉ संबंधी विवाद एक बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। इससे न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में वृद्धि होती है। एक एकीकृत संहिता संभावित रूप से इस बोझ को कम कर सकती है। समर्थकों का यह भी तर्क है कि समान नागरिक संहिता नागरिक मामलों में धार्मिक पहचान की तुलना में नागरिकता पर बल देकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगी। सभी समुदायों के लिए समान दंड संहिता का सफल कार्यान्वयन इस बात का उदाहरण है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में एक एकीकृत कानून किस प्रकार कार्य कर सकता है।

(शेष अगले कॉलम में)

## ससेका

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभकार हैं।



देश के विभिन्न हिस्सों से हाल के दिनों में ई-रिक्शाओं के अचानक बढ़ हो जाने अथवा उनके संचालन में व्यवधान आने की शिकायतों ने एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि कुछ मोबाइल ऐप्स या डिजिटल माध्यमों के जरिए इन वाहनों के संचालन को प्रभावित किया गया। सरकार द्वारा ऐसे कुछ सदिग्ध ऐप्स को हटाने या उनके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए जाने की खबरों ने इस विषय को और गंभीर बना दिया है। यद्यपि इन घटनाओं की जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा, फिर भी यह घटनाक्रम एक बड़े प्रश्न की ओर अवश्य संकेत करता है—क्या भारत की तेजी से डिजिटल होती अर्थव्यवस्था और परिवहन व्यवस्था साइबर हमलों के प्रति पर्याप्त रूप से सुरक्षित है?

आज ई-रिक्शा केवल एक वाहन नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका का आधार है। इनमें से अनेक वाहन मोबाइल ऐप, क्लाउड सर्वर, जीपीएस, बैटरी प्रबंधन प्रणाली और दूरस्था (रिमोट) सॉफ्टवेयर अपडेट जैसी तकनीकों पर निर्भर हैं। यदि इनमें किसी प्रकार की सुरक्षा कमजोरी हो, तो केवल एक वाहन ही नहीं, बल्कि हजारों वाहन एक साथ प्रभावित हो सकते हैं।

दुनिया में पहले भी ऐसे उदाहरण सामने आ चुके हैं, जब साइबर हमलों ने बिजली ग्रिड, तेल पाइपलाइन, अस्पताल, बंदरगाह, बैंकिंग सेवाओं

## किसी बड़े डिजिटल खतरे की चेतावनी

और दूरसंचार नेटवर्क को प्रभावित किया। इससे स्पष्ट है कि आधुनिक युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि डिजिटल नेटवर्क के भीतर भी लड़े जा सकते हैं। ऐसे में यदि किसी देश के छोटे-छोटे डिजिटल तंत्रों की सुरक्षा कमजोर हो, तो वे बड़े हमलों के लिए आसान



लक्ष्य बन सकते हैं। हालांकि यह कहना कि ई-रिक्शाओं की घटनाएँ निश्चित रूप से किसी बड़े साइबर युद्ध की 'रिहर्सल' हैं, अभी तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा। लेकिन सुरक्षा विशेषज्ञ लंबे समय से यह चेतावनी देते रहे हैं कि हमलावर अक्सर पहले छोटे स्तर पर कमजोरियों की पहचान करते हैं, फिर बड़े और महत्वपूर्ण तंत्रों को निशाना बनाते हैं। इसलिए ऐसी हर

घटना को गंभीरता से लेकर उसकी वैज्ञानिक और निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

भारत में डिजिटल भुगतान, स्मार्ट मीटर, इंटरनेट से जुड़े वाहन, ड्रोन, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, रेलवे, मेट्रो, अस्पताल और सरकारी सेवाएँ तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर होती

जा रही हैं। यह परिवर्तन सुविधाजनक और विकासोन्मुख है, लेकिन इसके साथ साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ जाती है। यदि किसी महत्वपूर्ण डिजिटल तंत्र में सेंध लगती है, तो उसका प्रभाव केवल तकनीकी नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा तक पहुँच सकता है।

इसके अतिरिक्त, साइबर घटनाओं की त्वरित रिपोर्टिंग, डिजिटल फॉरेंसिक जांच, स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट तथा नागरिकों और वाहन चालकों में साइबर जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अक्सर छोटी-सी लापरवाही बड़े संकट का कारण बन जाती है।

डिजिटल भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम सुविधाओं के साथ सुरक्षा को कितना महत्व देते हैं। तकनीक जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, उसकी सुरक्षा उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। ई-रिक्शाओं से जुड़ी हालिया घटनाएँ चाहे अंततः तकनीकी खराबी सिद्ध हों या साइबर हस्तक्षेप, उन्होंने एक महत्वपूर्ण चेतावनी अवश्य दी है—डिजिटल अवसरंचना की सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का अभिन्न अंग बन चुकी है।

घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता अवश्य है। यही सतर्कता भविष्य के संभावित डिजिटल संकटों को टालने का सबसे प्रभावी उपाय सिद्ध हो सकती है।

इसलिए अब साइबर सुरक्षा को केवल आईटी

विभाग का विषय मानना पर्याप्त नहीं है। वाहन निर्माता कंपनियों को अपने सॉफ्टवेयर का नियमित सुरक्षा परीक्षण करना चाहिए। रिमोट कंट्रोल और ऐप आधारित सुविधाओं में मजबूत एन्क्रिप्शन, बहु-स्तरीय प्रमाणीकरण और सुरक्षित अपडेट प्रणाली अनिवार्य होनी चाहिए। सरकार को भी इंटरनेट से जुड़े वाहनों और अन्य स्मार्ट उपकरणों के लिए स्पष्ट साइबर सुरक्षा मानक लागू करने चाहिए। साथ ही, सदिग्ध ऐप्स, विदेशी सर्वरों और अपूर्ण श्रृंखला (स्पलाइ चैन) से जुड़े जोखिमों की सतत निगरानी आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, साइबर घटनाओं की त्वरित रिपोर्टिंग, डिजिटल फॉरेंसिक जांच, स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट तथा नागरिकों और वाहन चालकों में साइबर जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अक्सर छोटी-सी लापरवाही बड़े संकट का कारण बन जाती है। डिजिटल भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम सुविधाओं के साथ सुरक्षा को कितना महत्व देते हैं। तकनीक जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, उसकी सुरक्षा उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। ई-रिक्शाओं से जुड़ी हालिया घटनाएँ चाहे अंततः तकनीकी खराबी सिद्ध हों या साइबर हस्तक्षेप, उन्होंने एक महत्वपूर्ण चेतावनी अवश्य दी है—डिजिटल अवसरंचना की सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का अभिन्न अंग बन चुकी है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता अवश्य है। यही सतर्कता भविष्य के संभावित डिजिटल संकटों को टालने का सबसे प्रभावी उपाय सिद्ध हो सकती है।

## हमारे अनिल, सबके अनिल

स्रण

श्याम बोहरे

दोड़ में फिर से भाग सके। मेरे सारे अवशेषों को जलाकर भस्म को हवा में बिखेर दिया जाए ताकि कुछ फूल खिल सकें।

रॉबर्ट एन. टेस्ट की ये पॉकियाँ अनिल ने किसी अस्पताल में लिखी देखी थीं और हमने अनिल के दिलो-दिमाग में। 'सुन रहे कि वक्त-जरूरत काम आए' से साधारण उदाहरण अनिल यादव के अनेकों परिचयों में से एक, मानवीय सरोकारों का परिचय देते हैं। अलबत आईस्टाइन ने महात्मा गांधी के लिए कहा था कि आने वाली पीढ़ियाँ यह भरोसा नहीं कर पायेंगी कि इस धरती पर हाड़-मांस का एक ऐसा इंसान भी हुआ था। मैं अनिल के लिए यह नहीं कहूँगा क्योंकि महात्मा केवल पूजे जाते हैं और व्यवहारिक काम के अधिक नहीं रह जाते। हमारे अनिल तो छोटे से कस्बे गंजबासोदा की धरती पर जीते जागते ऐसे मुकमिल इंसान रहे हैं, जो अपने साधारण कामों की असाधारण खुशबू बहुत दूर-दूर तक फैला गए। अनिल यदि महान होते तो वे आमजन के इतने करीब, इतने अपने, इतने दुखों, भाई साब, दाऊ, मित्र, सहयोगी, सहकर्मी कैसे होते? अनिल हमें यह बता गए कि राजपथ नहीं पगडंडी ही शिखर तक जाती है।



## सहकारिता मंत्रालय के 5 साल

डॉ. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक भारत के राष्ट्रपति के ओएसडी रह चुके हैं। हजारों केंद्रीय विश्वविद्यालय में वेपर प्रोफेसर हैं।



सहकारिता मनुष्य की उस सहज प्रवृत्ति का विस्तार है जिसमें 'मैं' का विस्तार होकर 'हम' बन जाता है। सहकारिता प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहभागिता, स्वार्थ के स्थान पर समर्पण और पूँजी के स्थान पर व्यक्ति की गरिमा को प्रतिष्ठित करती है। कहते हैं विकास का सबसे स्थायी मार्ग वही है, जिसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति भागीदार बने। सबकी उन्नति हो। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2026 की थीम थी-शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिताएँ, जिसका आशय ही है कि शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं, बल्कि न्याय, समान अवसर, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक विश्वास की स्थापना भी है। पश्चिम में सहकारिता का आधुनिक इतिहास 1844 में इंग्लैंड के रोचडेल नगर से प्रारंभ माना जाता है, जहाँ 28 श्रमिकों ने मिलकर एक उपभोक्ता सहकारी संस्था की स्थापना की थी। यह प्रयोग इतना सफल हुआ कि आज सहकारिता एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुका है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आज विश्व में लगभग 30 लाख सहकारी संस्थाएँ कार्यरत हैं, जिनसे 12 प्रतिशत से अधिक वैश्विक आबादी जुड़ी है तथा लगभग 28 करोड़ लोगों को रोजगार या कार्य के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। यह आँकड़ा स्पष्ट करता है कि सहकारिता किसी वैकल्पिक व्यवस्था का नहीं, बल्कि मानव विकास की मुख्यधारा का प्रतिनिधित्व करती है। सहकारिता का मूल दर्शन अधिकार एवं कर्तव्य में

## सहकारिता है आत्मनिर्भर भारत की यात्रा

अंतर्निहित है। इस दर्शन में स्वेच्छ व लोकतन्त्र विद्यमान हैं। लाभ का उपयोग केवल निजी समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि सामुदायिक विकास, शिक्षा तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए है। सहकारी संस्थाएँ समाज में विश्वास, उत्तरदायित्व और साझेदारी की संस्कृति विकसित करती हैं। दुनिया के अनेक देशों में सहकारिता ने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की नई इबारत लिखी। यूरोप के डेयरी उद्योग, जापान के कृषि संगठन, कनाडा की वित्तीय सहकारी समितियाँ और अफ्रीका के महिला स्व-सहायता समूह इस बात के प्रमाण हैं कि जब लोग संगठित होकर अपने संसाधनों का लोकतांत्रिक प्रबंधन करते हैं, तब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचता है। आज सहकारिता केवल कृषि या बैंकिंग तक सीमित नहीं है; स्वास्थ्य, आवास, ऊर्जा, शिक्षा, डिजिटल सेवाओं और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है।

यदि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत को देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि सहकारिता हमारी सांस्कृतिक चेतना का स्वाभाविक अंग रही है। भारतीय जीवनदर्शन में संगच्छ्वं संवदधं यानि साथ चलो, साथ सोचो जैसे जीवन आचरण के महामंत्र सहकारिता की आत्मा है। लोकहित की परंपराएँ भारतीय समाज में सदियों से विद्यमान रही हैं। आधुनिक भारत ने इन्हीं मूल्यों को संस्थागत स्वरूप देकर सहकारी आंदोलन को नई दिशा प्रदान की गई है इस दृष्टि से पाश्चात्य सहकारिता दृष्टि से भारतीय सहकारिता दर्शन प्राचीन है।

भारतीय सहकारिता की सबसे उज्ज्वल कहानी अमूल से प्रारंभ होती है। गुजरात के छोटे-छोटे दुग्ध उत्पादकों

द्वारा स्थापित यह सहकारी आंदोलन आज विश्व के सबसे सफल डेयरी मॉडलों में गिना जाता है। इसने न केवल किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाया, बल्कि भारत को दुग्ध उत्पादन में विश्व का अग्रणी राष्ट्र बना दिया। इसी प्रकार इफको ने उर्वक क्षेत्र में किसानों की भागीदारी को सशक्त बनाया और कृषि उत्पादन को नई गति प्रदान की। हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सहकारी संस्थाओं की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ी है।

भारत सरकार ने सहकारिता को राष्ट्रीय विकास की धुरी बनाने के उद्देश्य से पृथक सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की जिसके आज पाँच वर्ष पूरे हो रहे हैं। सहकार से समृद्धि केवल सरकारी नारा नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का व्यापक दृष्टिकोण है। विगत पाँच वर्षों में केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में प्राथमिक कृषि समितियों का सुदृढ़ीकरण, डिजिटल आधुनिकीकरण, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का विस्तार तथा महिलाओं और युवाओं की सहभागिता बढ़ाने जैसे प्रयास इस दिशा में उल्लेखनीय हैं। इन पहलों का उद्देश्य केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और सहभागी भारत का निर्माण है।

स्त्री सशक्तीकरण के क्षेत्र में सहकारिता ने परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। स्वयं सहायता समूहों, डेयरी समितियों, हस्तशिल्प संगठनों तथा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं ने लाखों महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान की। आर्थिक स्वतंत्रता ने उन्हें सामाजिक सम्मान, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व का अवसर दिया। यही

वह परिवर्तन है जिसे संयुक्त राष्ट्र समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की आधारशिला मानता है। सामाजिक न्याय की भागीदारी की नई इबारत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने लिखी है।

सहकारिता के लोकतंत्र की व्यावहारिक पाठशाला में आज खुशाहली है। यहाँ प्रत्येक सदस्य निर्णय प्रक्रिया में भाग लेता है, उत्तरदायित्व साझा करता है और सामूहिक हित को व्यक्तिगत लाभ से ऊपर रखता है। यही संस्कृति समाज में विश्वास का निर्माण करती है। वर्तमान समय में जब विश्व असमानता, बेरोजगारी, सामाजिक विभाजन और पर्यावरणीय संकट जैसी चुनौतियों से जुड़ा रहा है, तब सहकारिता इन समस्याओं का मानवीय और टिकाऊ समाधान सहकारिता विश्वविद्यालय के माध्यम से ढूँढने जा रही है। अनेक सहकारी संस्थाएँ राजनीतिक हस्तक्षेप, पारदर्शिता की कमी, सीमित पूँजी, तकनीकी पिछड़ेपन और कमजोर प्रबंधन जैसी समस्याओं से प्रभावित होती हैं, इससे अमित शाह ने अपनी दूरदर्शिता से निकाला है और पाँच वर्ष में ही युवा वर्ग का अपेक्षित जुड़ाव भी सुनिश्चित किया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक प्रबंधन, डिजिटल तकनीक, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा पारदर्शी प्रशासन को सहकारी व्यवस्था का अभिन्न अंग बनाया गया। अब सहकारिता अपनी मूल भावना को बनाकर नवाचार करे हुए नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बन सकेगी।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का मानना है कि सहकारी संस्थाएँ सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गरीबी उन्मूलन, भूखमुक्त

विश्व, लैंगिक समानता, सम्मानजनक रोजगार, असमानताओं में कमी और सामाजिक समावेशन जैसे अनेक लक्ष्यों की पूर्ति में सहकारिता प्रभावी माध्यम सिद्ध हो सकती है। भारतीय सहकारिता प्रणाली मानवीय विकास और संवेदना परस्पर पूरक मानती है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सहकारिता को सामाजिक संस्कृति के रूप में विकसित किया जाए। इससे समावेशी विकास संभव होगा। सहकारिता का भविष्य डिजिटल नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था, सामाजिक उद्यमिता, शिक्षा, कौशल विकास और स्थानीय आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ है। इसके लिए सुदृढ़ पॉलिसीज तैयार हों। सहकारिता-दृष्टि के संदेश को हम और ठीक समझें।

भारत में इस समय लगभग लाखों सहकारी संस्थाएँ हैं जिनके जरिए आर्थिक विकास और लोगों के सशक्तिकरण में सहयोग मिल रहा है। अमित शाह ने जो प्रयास दिल से किया है और सहकारिता को विगत पाँच वर्षों में एक सशक्त मंत्रालय और व्यवस्था के रूप में स्थापित किया वह असाधारण है। उनकी इच्छा है कि भारत में हर राज्य सहकारिता के माध्यम से समृद्ध भारत का निर्माण करें और विश्व में विकसित भारत की एक नई छवि बनाएँ। निःसंदेह विश्व में सहकारिता के लिए जो देश बहुत सक्रिय होकर काम करना शुरू किये वे भी भारत के सहकारिता मंत्रालय द्वारा लिए गए इनिशिएटिव और परिणाम तक नहीं पहुँच सकते। भारत ने कम समय में बहुत सी उपलब्धियाँ हासिल किया है और आने वाले वर्षों में यदि गतिशीलता यू ही बनी रही तो दुनिया में भारत का सहकारिता मॉडल अपनाया जाने लगेगा।

## पुस्तक इन दिनों

विजय जोशी

पूर्व गुप महाप्रबंधक, भेल

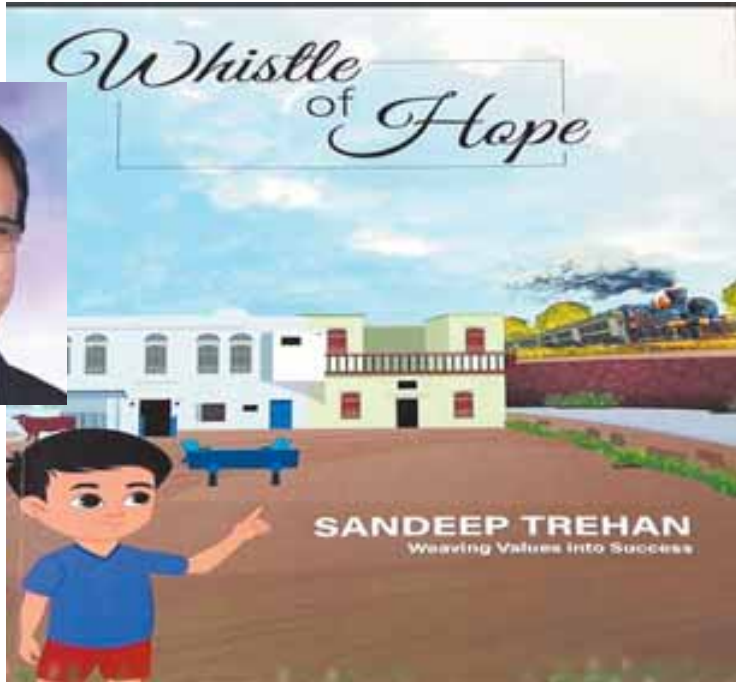


गतिशीलता का बाना ओढ़े इस वॉट्सऐपी दौर में अच्छा लेखन या पठन दोनों दोयम दर्जे पर आ गए हैं। ऐसे में यदि लीक से हटकर कुछ सारगर्भित पढ़ने को मिल जाए तो बात अनूठी हो जाती है। यही अनुभव उलब्ध है संदीप त्रेहन, प्रेसीडेंट, थिंक गैस की जमीनी हकीकत से जुड़ी आत्मकथा 'व्हिसल ऑफ होप में', जिसमें लेखक ने अपने जीवन अनुभव पूरी साफगोई और सच्चाई के साथ उक्रे हैं - राजस्थानी ग्राम किशनगढ़ में जन्मे लेखक का लालन पालन ऐसे से संयुक्त परिवार में हुआ जहां पैसा सीमित पर प्रेम अद्भुत था। दादी की पौराणिक कहानियों से संस्कारित मूल्यों की सुदृढ़ नींव। आरंभिक शिक्षा हिंदी माध्यम से सुविधा वंचित सरकारी स्कूल में पेड़ों की छांव तले। उस दौर में था पोस्टकार्ड संवाद का और आकाशवाणी एकमात्र मनोरंजन का साधन। इसी में अगले पृष्ठों पर संग्रहित हैं फूल की

अभिलाषा, झांसी की रानी, प्रेमचंद कहानी के उद्धरण इत्यादि देवनागरी में।

दूसरे चरण में समाहित है जयपुर से इंजीनियरी शिक्षा हेतु जीवन का दूसरा आयाम जहां हिंदी की आधारशिला पर अंग्रेजी में पढ़ाई का परिवर्तन काल। पढ़ाई के साथ ही दोस्तों की चुहलबाजी सहित प्रोजेक्ट के अंतर्गत टीमवर्क का पाठ।

तीसरे में वर्णित है नौकरी के आरंभिक अनुभव कदम दर कदम। भूगर्भीय ईंधन स्रोत में लेखक की रुचि को धार मिली मुंबई में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन में प्रवेश के साथ



जब उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में भी प्रेस वाली इस्त्री से पापड़ सेंकने एवं गोजर के गर्म पानी से कॉफी बनाने की कला सीखीं। कम्पनी टीम की ओर से क्रिकेट खेलते हुए तत्कालीन अनेक इंडियन क्रिकेटरों से भेंट। आला अध्येय समर्पित है रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स में लेखक का भूगर्भीय तेल उत्खनन संबंधी वह ज्ञान जिसकी सहायता से गुजरात में पहली बार तेल खोज के एक महती अभियान को सफलता प्राप्त हुई। इसका विस्तृत तकनीकी विश्लेषण इस अध्याय में उपलब्ध है। और उपरोक्त समस्त ज्ञान, अनुभव के प्रतिबद्धता पूर्ण प्रयासों के निचोड़ स्वरूपी परिणाम फलित हुआ रसोई गैस

की घर पहुंच महीती सेवा को समर्पित कम्पनी 'थिंक गैस' की एक दशक पूर्व स्थापना द्वारा, जिसका मिशन स्टेटमेंट है - 'आपकी सेवा आपके द्वार'। इसके अंतर्गत अब तक 4700 वर्ग किलोमीटर में स्थापित पाइपलाइन द्वारा 5 प्रदेशों में 18 लाख नागरिकों के रसोई घर तक निर्बाध प्रदायगी सुनिश्चित की गई है। मजदूर बात यह भी है कि इनके कॉरपोरेट कार्यालय में केबिन मुक्त व्यवस्था सहित सब मित्रवत एक साथ एक छत के नीचे काम करते हैं। समाजवाद, सहभागिता एवं टीमवर्क। और अंत की सबसे सुखद बात यह कि इस पुस्तक में लेखक का खेहिल मानवतावादी पक्ष भी पूरी संवेदनशीलता के साथ उभरा है, जिसके अंतर्गत अभिभावक, सहधर्मिणी, बच्चे, मित्र मंडली से लेकर हर नगर में विद्यमान दोस्तों का भावभीना समायोजन है निर्मल मन सहित। पुस्तक का मुखपृष्ठ चेतक घर। अनुभव एवं यादों का सुंदर समायोजन। रोचक शैली। उत्तम मुद्रण। गागर में सागर

## उप मुख्यमंत्री ने संस्कृत विश्वविद्यालय भवन निर्माण का लिया जायजा



भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा में निर्माणाधीन महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के परिसर भवन के निर्माण का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विन्ध्य क्षेत्र परंपरागत रूप से संस्कृत विद्या का केन्द्र रहा है। यहाँ कई गांवों में संस्कृत विद्यालय अभी भी संचालित हो रहे हैं। संस्कृत देवभाषा होने के साथ-साथ प्राचीन

ज्ञान, विज्ञान और सनातन की भाषा है। विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण होने से रीवा संस्कृत भाषा के केन्द्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। उप मुख्यमंत्री ने इंजीनियरों तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को निर्माण कार्यों के संबंध में निर्देश दिए। निरीक्षण के समय संबंधित अधिकारी तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

## स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान से देश को आजादी मिली है: उप मुख्यमंत्री

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार संगठन के सम्मेलन का शुभारंभ किया। कृष्णा राजकपुर आडिटोरियम में रीवा में आयोजित सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान से देश को आजादी मिली है। लाखों देशभक्तों ने भारत माता को परतंत्रता की बेड़ी से मुक्त करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। तुर्क, मुगल, डच, पुर्तगाली और अंग्रेज भारत की समृद्धि और संपदा को लूटने तथा राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के लिए आए थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अनगिनत यातनाएं सहकर हमें गुलामी से मुक्त कराया। उनके परिवारजनों को सम्मानित करके हम सबको गौरव का अनुभव हो रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2047 तक देश को विश्वगुरु बनाने का संकल्प लिया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश को स्वतंत्र करने के बाद जिस चहुँमुखी प्रगति का सपना देख रहे थे उसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। भारत तेजी से प्रगति करता हुआ ग्यारहवें स्थान से विश्व की चौथी सबसे बड़ी

अर्थव्यवस्था बन गया है। यह 2047 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में ही भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी भारत की होगी। देश और प्रदेश में तेजी से किए जा रहे विकास के कार्य और निरंतर प्रगति इस भविष्यवाणी को सच करने का प्रयास कर रहे हैं। जल जीवन मिशन से हर गांव के हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। गौपालन और प्राकृतिक खेती को अपनाकर हम आमजनों को विषमक अनाज देने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। गरीबों को पानी, बिजली, निःशुल्क अनाज, उपचार की सुविधा और पक्के मकान जैसे लाभ देकर सबका उत्थान किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कार्यों को नगरों के प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा जिससे नई पीढ़ी उनके त्याग और बलिदान से परिचित हो सके। सम्मेलन में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव श्री जितेन्द्र रघुवंशी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश के लिए अपना सर्वस्व त्यागकर कर दिया। उनके परिवारजनों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए भटकना पड़ रहा है। नई पीढ़ी को आजादी की लड़ाई के इन वीरों की गाथा से परिचित कराने का प्रयास होना चाहिए।

## कचरा उत्पादक संस्थानों को कराना होगा पंजीयन

नियमों का करना होगा पालन, उल्लंघन पर भरना होगा प्रतिदिन 200 रुपए जुर्माना

बैतूल। कचरा प्रबंधन को लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बेहद गम्भीर है। मंत्रालय ने नगर पालिका और परिषदों को इस संबंध में पत्र लिखकर कचरा प्रबंधन के लिए सभी को प्रेरित करने एक नियमावली जारी की है और इसके साथ ही इसका पालन करना अनिवार्य किया है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ प्रतिदिन 200 रुपए या इससे अधिक का जुर्माना करने आदेश जारी किए हैं। नगर परिषद बैतूल बाजार के सीएमओ नलिन चिंचलवार ने इस पत्र का हवाला देते हुए बताया कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 अधिसूचित किए गए हैं, जो 01 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि निकाय सीमा क्षेत्र अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 लागू कर दिए गए हैं। उक्त नियम के नियम क्रमांक 3 (अ)(आई), 6 एवं 10 में थोक कचरा उत्पादक की श्रेणी के



लिए वर्णित परिभाषा एवं प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार भारी मात्रा के अपशिष्ट जनिष्ठ हैं, जो इन मानकों में से कम से कम एक को पूरा करते हो, जैसे 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भवन, या प्रतिदिन 40,000 लीटर पानी की खपत, या प्रतिदिन 100 किलोग्राम ठोस अपशिष्ट उत्पादन व निकाय सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले

मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेट, धर्मशाला, छात्रावास, सामुदायिक भवन, रहवासी संघ एवं अन्य संस्थान आदि, जो कम से कम एक मानदंड को पूरा करते हैं, वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम-2026 के अनुसार थोक कचरा उत्पादक की श्रेणी में माने जाएंगे। ऐसे थोक कचरा उत्पादकों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम-2026 का पालन करना अनिवार्य है।

संबंधित पर लगेगा 200 रुपए प्रतिदिन अर्थदंड..

संस्थान से निकलने वाले सूखे एवं अन्य अपशिष्ट को निकाय के अधिकृत कचरा संग्रहक को सौंपना होगा। प्रतिदिन प्रसंस्कृत किए गए गीले अपशिष्ट एवं उत्पन्न खाद की लॉग बुक का संधारण करना, यदि संस्थान अपने परिसर में ही गीले कचरे का प्रसंस्करण करने में असमर्थ है, तो नियमानुसार निकाय अथवा निकाय द्वारा अधिकृत संस्थान से गीले कचरे के प्रसंस्करण के लिए अनुबंध कर निकाय से विस्तारित थोक अपशिष्ट जनिष्ठ उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के नियम क्रमांक 6 एवं 10 में वर्णित समस्त प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सभी थोक कचरा उत्पादक अपने परिसर में ही कचरे का निपटारा किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा निकाय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड भी अधिरोपित किया जाएगा।

इनका कहना है -

कचरा प्रबंधन के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का पालन कराना अनिवार्य है। कचरा प्रबंधन ना होने पर जुर्माना करने के आदेश भी दिए गए हैं।

- नलिन चिंचलवार, सीएमओ, नगर परिषद बैतूलबाजार, जिला बैतूल

## 2010 से पूर्वनियुक्त शिक्षकों को टेट से छूट देने की मांग

संयुक्त मोर्चा ने केंद्रीय राज्यमंत्री डी.डी.

उड़के को सौंपा ज्ञापन

बैतूल। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले वर्ष 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को लेकर बैतूल जिले के शिक्षा विभाग के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एक-जुट होकर आवाज बुलंद की। रविवार 5 जुलाई को संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने अनुसूचित जनजाति केंद्रीय राज्यमंत्री डी.डी. उड़के के गृह निवास पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार से इस संबंध में नया अध्यादेश पारित कराने का आग्रह किया। ज्ञापन में मांग की गई कि वर्ष 2010 के पूर्व से नियुक्त शिक्षकों को टेट परीक्षा की बाध्यता से मुक्त किया जाए तथा संसद के आगामी मानसून सत्र में इस संबंध में नया अध्यादेश लाकर लंबे समय से लंबित मांग का समाधान किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाना आवश्यक है। संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सचिन राय, भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष पंजाब गायकवाड, आरंभ शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कटार, ट्रॉईबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष प्रवीण नखरे, पुरानी पेंशन बहाली के जिला अध्यक्ष रवि सरकर, राज्य अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष भीमवार धोटे, आजाद अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष विनय सिंह राठौड़, अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष मदनलाल उडोरे, कोषाध्यक्ष प्रकाश सिंह देवडे, राजू अटनोरे, मुकेश उपराले, योग शिक्षक रंजीत धुर्वे सहित अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय राज्यमंत्री से शिक्षकों की मांग को संसद तक पहुंचाने और उसके शीघ्र निराकरण के लिए आवश्यक पहल करने का आग्रह किया।

## सोहागपुर सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न



सोहागपुर। विश्व की सबसे बड़ी गैर राजनीतिक छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग आज मुदुल नाथ चौहान विभाग संयोजक के मुख्य आतिथ्य एवं यशवंत दुबे मुख्य वक्ता प्रांत कार्यकारिणी सदस्य मुख्य वक्ता के आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रांत कार्यकारिणी सदस्य यशवंत दुबे ने संगठन की कार्य कौशल रीति नीति अंगत करते हुए प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ता व्यवहार, दायित्व बोध चार विषयों पर बौद्धिक सत्रों के माध्यम से संगठन की रीति नीति कार्य पद्धति को प्रत्येक कार्यकर्ता प्रशिक्षित किया गया। इसी अवसर पर निवृत्तमान नगर मंत्री राहुल रघुवंशी ने वार्षिक मनोवृत्त रखा। मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता मुदुल नाथ चौहान ने नवीन घोषणाओं में नगर अध्यक्ष प्राध्यापक अल्पना उपाध्यक्ष, नगर मंत्री ऋषि मेहरा, उपाध्यक्ष राश राहुल साहू, कपिल, आयुष रघुवंशी, सह मंत्री कार्तिक सराटे, लकी साहू, मयंक साहू, आदर्श सिंघानिया के अलावा कार्तिक यादव, निहाल प्रजापति, केशव रघुवंशी अनुज इसरानी, अरुण रघुवंशी, कौशल चौहान, चमन गुर्जर मनमोहन, प्रांशु रघुवंशी, लकी आशु राजपूत, लोकेश नागेश, शिवांश रघुवंशी आदि कार्यकर्ताओं को प्रमुख दायित्व दिए गए। सभी नवीन पदाधिकारियों का फूलमालाओं से स्वागत किया गया।

## माखननगर पुलिस थाने के अंतर्गत ग्राम में 25 प्रतिशत मृग खरीदी के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, फूका कृषि मंत्री का पुतला

सोहागपुर। प्रदेश के मात्र 25 प्रतिशत मृग खरीदी के सरकारी फैसले का विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम जगह जगह किया जा रहा है। इसी क्रम माखन नगर पुलिस थाने के अंतर्गत ग्राम मेरे में नारेबाजी के साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आदि के पुतलों का दहन किया गया। जिसमें आंदोलन कारियों के पुतला दहन के उपरांत पुलिस कारियों ने पुतलों को छीनने की कोशिश की गई वहीं पुलिस कारियों ने पुतलों पर पानी डालने को लोग दौड़ पड़े। यहां कृषि मंत्री शिवराज सिंह



चौहान आदि के विरुद्ध मृग की शत-प्रतिशत खरीदी नहीं करने के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेता नीरज चौधरी ने बताया कि माखननगर सोहागपुर ब्लॉक में शत-प्रतिशत मृग खरीदी नहीं करने के विरोध में किसानों ने अपने आंदोलन को उग्र रूप देते हुए जगह-जगह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आदि के पुतलों का दहन किया जा रहा है। सरकार के इस रवैये, नीति के खिलाफ किसानों का गुस्सा सोहागपुर ब्लॉक के गुरा, गुजरखेड़ी और भोखेड़ी सहित कई अन्य गांवों में देखने को मिला। किसानों ने पुतला दहन कर शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी नाराजगी जाहिर की। इन अवसरों पर किसान नेता एवं सोहागपुर से पूर्व कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी पुष्पराज पटेल ने शासन-प्रशासन को चेतावनी दी है। कि सरकार, 'आगर सरकार जल्द ही किसानों की शत-प्रतिशत (100%) मृग की खरीदी शुरू नहीं करती है, तो पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन का यह सिलसिला यहीं नहीं थामेगा, बल्कि यह हर गांव और हर शहर में इसी तरह जारी रहेगा।' उल्लेखनीय है इस पुतलों दहन के एक दिन पूर्व कांग्रेस नेता पुष्पराज सिंह पटेल ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके ऐसे पुतलों के दहन करने का किसानों से आह्वान किया था।

# याद आर्येंगे स्वर और अभिनय कला के मौलिक अंदाज

आदरांजलि: तीजनबाई

अशोक मनवानी

प्रभारी संयुक्त संचालक, जनसंपर्क भोपाल



स्तर साल का कला और अभिनय से परिपूर्ण जीवन पूरा कर तीजन बाई पांच जुलाई को संसार से रखसत हो गईं। उन्हें सुनना एक आनंद प्रदक्ष से रूबक होना होता था। वे अविभाजित मध्य प्रदेश की गौरवशाली व्यक्तित्व थीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्यों के लिए ही नहीं पूरे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय थीं। उन्होंने विश्व स्तरीय हुनरमंद और होनहार कलाकार का दर्जा हासिल किया। लोक कला प्रेमियों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। मेरे दादा के गांव छत्तीसगढ़ के मुगेली

का जिक्र करता और उनसे जनसंपर्क के वरिष्ठ अधिकारी रहे और लोक कलाओं के मर्मज्ञ भाऊ खिरवडकर जी के साथ हुई प्रथम भेंट का भी स्मरण दिलवाता था तो वे मुस्कुुर देती थीं।

तीजन बाई अपनी कला यात्रा से संतुष्ट थीं नहीं। दरअसल उन्होंने पंडवानी कथा गायन कला में मौलिक शैली से कई नवाचार भी किये। रूप सज्जा और अभिनय के स्तर पर कई नवाचार भी किए। पंडवानी गायन की कला को समृद्ध किया, तभी तो वे विश्व विख्यात भी बन गईं।

लोक गाथाओं को सुनने की परम्परा- मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोक गाथाओं को सुनाने और एक या एकाधिक कलाकारों द्वारा मंच पर प्रस्तुत करने की समृद्ध परंपरा है। कला को समर्पित कलाकार प्रस्तुति से एक तरह के तिलिस्म की रचना कर देते हैं।

कर्नाटक का यक्षगान हो या सिंध प्रांत का भगत गायन, लोक गाथा गायन में पंडवानी का स्थान सबसे अलग



है। अनेक भाषाओं में लोक गाथाओं को गाया जाता है। बुंदेली में जगन्नाथ प्रजापति सुल्तानगंज जिला रायसेन ने डेला मारु, जो राजस्थान की प्रणय गाथा है उसे पूरे जीवन में सुनाया। पुरी कथा दो रातों में सुनाते थे। ग्रामीण बंधु रात भर जागकर और मित्रों को जाग कर सुनते सुनाते थे। उनकी कई पीढ़ियां इस कला से जुड़ी थीं। आज मध्य प्रदेश में ऐसी और भी आंचलिक बोलियां हैं जिनमें कथा गायन की परंपरा है। इस पर अनुसंधान होना चाहिए। ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ये आर्टिस्ट समाज की एक धरोहर को बचाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग और जनजातीय संग्रहालय ने इस दिशा में ठोस कार्य किया है।

लोकंरंग और भोजपुर उत्सव- मुझे याद आ रहा हूँ तीजन बाई का आखिरी कार्यक्रम, दो-तीन साल पहले उन्हें भोजपुर उत्सव में सुना था। एक समय था जब वे भोपाल लांगम हर साल ही आती थीं। रविंद्र भवन परिसर में लोक कलाओं के बहुरंगी मेले लोकंरंग समारोह यदि स्थापित हुआ

तो उसका श्रेय श्रीमती तीजन बाई जैसे कलाकारों को जाता है। दो दिन कार्यक्रम सात दिन अवधि तक जा पहुंचा। भोपाल में बसे छत्तीसगढ़ से संबंध रखने वाले नागरिक और यहां मजदूरी का कार्य करने वाले छत्तीसगढ़ी समुदाय के दर्शक, श्रोता भी तब सुनने आया करते थे।

अलग अंदाज रहेगा यादगार- जब तीजन बाई गाती थीं और कथा सुनाती थीं तो पंडवानी गायन में उनका एक संवाद याद आता है, जब उनका स्वर होता था... भगवान रामचंद्र बोलीस तो उनका सहयोगी कलाकार पूछता था का बोलीस ?

इसे सुन दर्शक, श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते थे। कला प्रेमियों को उनका ये अंदाज सदैव याद आएगा। महाभारत के द्रौपदी के चार हरण के प्रयाग को सुनाते वे उडेलित हो जाती थीं, नारी के स्वाभिमान और अस्मिता के विचार को मन में समाए वे अपनी भाव भंगिमाओं से समाज को दर्शना देने का कार्य करती थीं एक समर्पित कलाकार को श्रद्धा से नमन।

# एमपी के 24 जिलों पर मंडराया सूखे का खतरा

## सीएम के गृह संभाग उज्जैन में सबसे ज्यादा संकट- बीज, सिंचाई और फसल बदलने का प्लान तैयार

**भोपाल (नप्र)**। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून सामान्य से कम जोर रहने की आशंका के बीच राज्य सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के बाद सरकार ने 24 जिलों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर ली है।

सबसे अधिक चिंता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह संभाग उज्जैन को लेकर है, जहाँ सबसे अधिक वर्षा की कमी रहने की आशंका जताई गई है। सरकार ने इन जिलों में किसानों को कम पानी वाली फसलें अपनाने, वैकल्पिक बीज उपलब्ध कराने, सिंचाई और जल संरक्षण के इंतजाम बढ़ाने तथा जिला स्तर पर माइक्रो प्लान लागू करने की तैयारी कर ली है। राजस्व और कृषि विभाग ने सूखे जैसी स्थिति बनने से पहले ही राहत और बचाव की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।

**आखिर सूखे की आशंका क्यों पैदा हुई?** - आईएमडी ने मध्य प्रदेश में इस बार



सामान्य वर्षा का केवल 90 से 94 प्रतिशत होने का पूर्वानुमान दिया है। 1 जून से 1 जुलाई तक सामान्य 139.7 मिमी की तुलना में केवल 92.4 मिमी वर्षा हुई, यानी 47 मिमी

की कमी दर्ज की गई।

मानसून के दूसरे चरण में भी बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना जताई गई है। कई जिलों में पहले ही सामान्य से

20 से 60 प्रतिशत तक वर्षा घाटा दर्ज हो चुका है। यदि जुलाई और अगस्त में भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो खरीफ फसलों के उत्पादन पर सीधा असर पड़ सकता है।

**सरकार की सबसे बड़ी तैयारी क्या है?** - सरकार ने संभावित सूखे से पहले ही कृषि और राजस्व विभाग को संयुक्त कार्ययोजना लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 24 जिलों के लिए विशेष एडवाइजरी तैयार की गई है। सात जिलों में विस्तृत माइक्रो प्लानिंग होगी और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से लगातार तकनीकी निगरानी की जाएगी।

किसानों को मौसम के अनुसार खेती करने की सलाह मौसम, सोशल मीडिया और स्थानीय माध्यमों से दी जाएगी। जिला स्तर पर अधिकारियों को हालात की रोजाना समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।

### किसानों को क्या करना होगा?

सरकार किसानों को कम अवधि और कम पानी वाली फसलें अपनाने की सलाह देगी। दलहन, तिलहन और मोटे अनाज का रकबा बढ़ाने पर जोर रहेगा। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, वैकल्पिक फसल चयन कराया जाएगा। रिज एंड रेज्ड बेड और डायरेक्ट सीडिंग राइस जैसी वैज्ञानिक खेती तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि कम पानी में भी उत्पादन प्रभावित न हो।

### बीज और सिंचाई के लिए क्या इंतजाम होंगे?

सरकार ने वैकल्पिक फसलों के पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने और समय पर वितरण की योजना बनाई है। मनरेगा के माध्यम से खेत तालाब, जल संरक्षण और जल संचयन के निर्माण व मरम्मत पर काम होगा। उपलब्ध जल स्रोतों का अधिकतम उपयोग कराया जाएगा और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि कम पानी में भी खेती जारी रह सके।

### सूखा पड़ा तो सरकार क्या करेगी?

राजस्व विभाग ने वर्ष 2020 की सूखा नीति के अनुसार पूरी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। खरीफ फसलों के लिए 31 अक्टूबर तक और रबी फसलों के लिए 31 मार्च तक सूखे की घोषणा की जा सकेगी। विभाग के पास राहत कार्यों के लिए 20.9 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त राशि भी जारी की जाएगी। सभी जिलों से क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान तैयार करा लिए गए हैं और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है।

# ग्वालियर में बच्चों के क्रिकेट झगड़े में कूदा सनकी पिता

## 11 साल के मासूम पर बैट से किए ताबड़तोड़ वार, तोड़ डाले 3 दांत

**ग्वालियर (नप्र)**। जिले में बच्चों के बीच खेल-खेल में हुई मामूली कहसुनी एक खूनी और दर्दनाक वारदात में बदल गई। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के किरावली में एक सनकी पिता ने गुस्से में अपना आपा खोते हुए मैदान में खेल रहे 11 वर्षीय मासूम खिलाड़ी पर क्रिकेट बैट से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

आरोपी द्वारा किए गए वार इतने जोरदार और बर्बर थे कि बच्चे के सामने के तीन दांत टूट गए और उसका ऊपरी होंठ बुरी तरह फट गया। लहुलुहान हालत में मासूम को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज शुरू किया।

**बेट के हाथ से बैट छीना और सीधे चेहरे पर दे मारा-** ग्रांडजिरो से मिली जानकारी के मुताबिक, उटीला के किशनलाल का पुत्र निवामी रणवीर सिंह 2 जुलाई को सपरिवार अपनी बहन के घर किरावली आए हुए थे। शाम करीब 4:30 बजे उनका 11 साल का बेटा दिनेश गांव के अन्य बच्चों के साथ खेल में बने मैदान पर

### पुलिस के पास गए तो जान से मार दूंगा

हमले के बाद जब दिनेश जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, तब भी आरोपी का दिल नहीं पसीजा। जाते-जाते आरोपी बालकिशन बंजारा ने पीड़ित परिवार को सरेआम धमकी दी कि अगर इस मामले की शिकायत पुलिस में की, तो वह उन्हें जान से मार देगा। घटना के अगले दिन पीड़ित परिवार ने हिम्मत जुटाकर हस्तिनापुर थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी बालकिशन के खिलाफ मारपीट और गंभीर धारा के तहत केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

क्रिकेट खेल रहा था। इसी दौरान खेल के नियमों को लेकर दिनेश की राहुल बंजारा नाम के बच्चे से कहसुनी हो गई। विवाद की भनक लगते ही राहुल का पिता बालकिशन बंजारा गुस्से में तमतमाता हुआ सीधे मैदान पर पहुंच गया। उसने बिना कुछ सोचे-समझे अपने ही बेटे के हाथ से क्रिकेट बैट छीना और सीधे दिनेश के मुंह पर दे मारा।

# भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस 15 दिन कोटा नहीं जाएगी

## कोटा जंक्शन पर 15 दिन का मेगा ब्लॉक, कई ट्रेनें प्रभावित

**भोपाल (नप्र)**। कोटा जंक्शन पर स्टेशन पुनर्विकास कार्य के चलते 4 से 18 जुलाई तक 15 दिनों का ब्लॉक लिया जाएगा। इसका असर भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों पर पड़ेगा। इस दौरान कुछ ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले जाएंगे, कुछ परिवर्तित मार्ग से चलेंगी, जबकि कुछ मेमू ट्रेनों का संचालन सोगरिया स्टेशन से किया जाएगा।

रेल प्रशासन के अनुसार, प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर पुनर्विकास कार्य होने के कारण ब्लॉक अवधि में ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान में भी देरी हो सकती है। यात्रियों को निर्धारित समय से पहले स्टेशन पहुंचने और यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है।

**भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस 15 दिन कोटा नहीं जाएगी-** 18 जुलाई तक भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस (14814) और जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस (14813) कोटा जंक्शन की बजाय गुड़ला-कोटा चंबल केबिन-सोगरिया मार्ग से संचालित होंगी। दोनों ट्रेनें इन 15 दिनों तक कोटा स्टेशन पर नहीं आएंगी।



भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस सोगरिया स्टेशन पर रात 2.0 बजे पहुंचेगी और 2.20 बजे खाना होगी, जबकि जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस सोगरिया स्टेशन पर रात 11.30 बजे पहुंचेगी और 11.40 बजे प्रस्थान करेगी।

**दयोंदय एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म बदला-**

जबलपुर-अजमेर-जबलपुर दयोंदय एक्सप्रेस (12181/12182) और कोटा-बीना मेमू (11603) का संचालन ब्लॉक अवधि में प्लेटफॉर्म नंबर-4 के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर-3 से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर अन्य ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में भी बदलाव किया जा सकता है।

### बीना-कोटा मेमू सोगरिया तक ही चलेगी

बीना-कोटा मेमू (61634) 4 से 18 जुलाई तक कोटा जंक्शन नहीं पहुंचेगी और सोगरिया स्टेशन पर ही अपनी यात्रा समाप्त करेगी। वहीं कोटा-बीना मेमू (61633) इन 15 दिनों में कोटा जंक्शन की जगह सोगरिया स्टेशन से दोपहर 3:20 बजे खाना होगी।

### यात्रियों के लिए सलाह

रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन के प्लेटफॉर्म, समय और संचालन की ताजा जानकारी एनटीईएस एप, स्टेशन के डिस्पले बोर्ड या पूछताछ केंद्र से अवश्य प्राप्त करें। ब्लॉक के दौरान ट्रेनों के संचालन में देरी की संभावना को देखते हुए यात्रियों को समय से पहले स्टेशन पहुंचने की भी सलाह दी गई है।

# प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत 90 देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है : डॉ. मोहन यादव

## डॉ. मुखर्जी के बताए मार्ग पर चलकर भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना : हेमंत खण्डेलवाल

**भोपाल।** भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिवप्रकाश जी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल ने रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर स्मरण पत्र के तहत आयोजित जिला कार्यकारी सम्मेलन को संबोधित किया। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिवप्रकाश जी ने कहा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दूरदृष्ट थे, उनकी दूरदृष्टि के कारण आज का पश्चिम बंगाल भारत में बना रहा। आजादी के बाद पाकिस्तान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के लिए गलियारा मांगकर भारत के फिर टुकड़े करने की योजना में था। डॉ. मुखर्जी ने पाकिस्तान में हुई बाजचीत में देश के अंदर से तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के लिए गलियारा देने से मना कर पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बंटे रहने के लिए मजबूर किया, यह उनकी दूरदृष्टि का ही परिणाम है। डॉ. मुखर्जी का जीवन हम सभी के लिए स्मरणीय व प्रेरणादायी है। उनके बलिदान के कारण जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि युनिफिकेशन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर की स्वायत्ता के लिए अपना बलिदान दे दिया। वह जन्मजात प्रतिभा के धनी थे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जम्मू-कश्मीर से थारा 370 हटाकर डॉ. मुखर्जी का सपना



पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत चतुर्दिक विकास कर रहा है। आज भारत 90 देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अहम योगदान है। डॉ. मुखर्जी के विचारों ने राष्ट्रवादी राजनीति की मजबूत नींव रखी है। डॉ. मुखर्जी के बताए मार्ग पर चलकर भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है।

भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिवप्रकाश जी ने कहा कि आजाद भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सर्वदलीय सरकार में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री बनाए गए थे। भारत आज जिस

उद्योग नीति का अवलोकन कर विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, वह डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बनाई उद्योग नीति है। डॉ. मुखर्जी ने छोटे उद्योगों, लघु उद्योगों और बड़े उद्योगों के विकास के लिए एक संस्था की स्थापना की थी, वह संस्था है उद्योग विकास निगम। देश को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं, वह कार्य डॉ. मुखर्जी ने ही शुरू किया था। डॉ. मुखर्जी ने भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए हाथकरखा, व लघु उद्योगों की स्थापना का वृहद अभियान चलाया था। देश के आजाद होने के बाद भारत की शिक्षा प्रणाली को देश की भाषा में और रोजगारपरक बनाने के लिए भी डॉ. मुखर्जी ने कार्य किया, लेकिन जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए उनका बलिदान हो गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, उसे सबसे पहले डॉ. मुखर्जी ने ही लागू करने की योजना बनाई थी। वह अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे, 33 वर्ष की आयु में बंगाल के कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए थे। पहले दीक्षांत समारोह अंग्रेजी में हुआ करते थे। डॉ. मुखर्जी ने रबीन्द्रनाथ ठाकुर टैगोर को कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाकर बांग्ला भाषा में दीक्षांत समारोह आयोजित कराया। बांग्ला भाषा में रिसर्च की पुस्तक प्रकाशित कराने के साथ भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी उन्होंने आजादी के बाद देश में शुरू किया था।

भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिवप्रकाश जी ने कहा कि देश के आजाद होने के लिए लाखों की संख्या में लोगों ने बलिदान दिए, लेकिन देश के आजाद होने के बाद उसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए पहला बलिदान देने वाले महापुरुष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। डॉ. मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिपरिषद से डॉ. मुखर्जी ने इस्तीफा देने के कई कारण हैं, उनमें सबसे बड़ा और पहला कारण था कि नेहरू सरकार बहुसंख्यक वर्ग की सुरक्षा और सम्मान के लिए कोई ठोस कार्य नहीं कर रही थी।

# ग्वालियर में आरती मर्डर केस में खुलासा

## आरती अपने लिव इन पार्टनर संजु के साथ रहती थी, शादी के बाद पहले पति को छोड़ दिया

**ग्वालियर (नप्र)**। आरती हत्याकांड में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। मुख्य आरोपी धर्मेद को गिरफ्तार कर लिया है। धर्मेद आरती का लिव इन पार्टनर था। उसने पूछताछ के दौरान बताया है कि वह बहुत अकड़ती थी। गला दबाया तो वह एक मिनट भी झेल नहीं पाई और छटपटाकर वहीं दम तोड़ दिया।

**नाम मेरा और रहती दूसरे के साथ-** धर्मेद इस बात से नाराज था कि आरती ने उसे धोखा दिया। आधार कार्ड से लेकर सरकारी दस्तावेजों तक पर धर्मेद का नाम था। लेकिन धर्मेद के फुफेरे भाई संजु से उसका संबंध हो गया तो वह उसी के साथ रहने लगी। यह सब धर्मेद से सहन नहीं होता था। इसके बाद उसने यह कदम उठा लिया।

**एक घंटे से ज्यादा नहीं ठहरता किसी जगह-** आरती की हत्या के बाद धर्मेद ग्वालियर पुलिस को लगातार चकमा देता रहा है। मोबाइल लोकेशन से उसका पीछा नहीं हो। इसकी वजह से वह एक घंटे से ज्यादा देर तक कहीं नहीं ठहरता था। हालांकि पुलिस को यह जानकारी मिली कि आरोपी तलवार वाले हनुमान मंदिर के पीछे छुपा हुआ है। इसके बाद घेराबंदी कर उसे दबोच लिया गया। पुलिस के सामने उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

**तीसरे के साथ रह रही थी आरती-** जांच के

दौरान यह जानकारी मिली है कि आरती ने 11 साल में दो मर्दों को छोड़ दिया था अब तीसरे साथ वह लिव इन में रह रही थी। आरती ने शादी के बाद अपने पहले पति को छोड़ दिया। इसके बाद वह धर्मेद के साथ रहने लगी थी। कुछ दिन बाद धर्मेद को छोड़कर संजु के साथ रहने लगी।



**2015 में हुई थी पहली शादी-** आरती की पहली शादी 2015 में हुई थी। यह शादी अतर सिंह से हुई थी, उससे दो बच्चे हुए थे। पति के दोस्त से धर्मेद से उसकी नजदीकियां बढ़ीं और 2023 से उसके साथ रहने लगी। फिर सभी दस्तावेजों में धर्मेद के नाम जुड़ा लिए। कुछ दिनों बाद धर्मेद से विवाद हुआ और संजु के साथ रहने लगी।

**एक जुलाई को हुई हत्या-** एक जुलाई को हजौरा थाना क्षेत्र के आरा मील इलाके में आरती की हत्या हुई थी। हत्या धर्मेद ने की थी। उस वक्त मौके पर संजु भी मौजूद था। तीनों साथ में बैठकर पहले शराब पी थी।

# होटल में तलवार-चाकू लेकर घुसे 15 बदमाश

## चार युवकों पर हमला, शोफ और कर्मचारियों से भी मारपीट

**भोपाल (नप्र)**। भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र के बंगरसिया-भोजपुर रोड स्थित जैन ब्रदर्स होटल में शनिवार रात 10 से 15 बदमाश तलवार, चाकू, हॉकी और बेसबॉल बैट लेकर घुस आए। बदमाशों ने होटल में तोड़फोड़ करके हुए चार युवकों पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे होटल के शोफ और अन्य कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की। पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

हमले में गंभीर रूप से घायल 24 वर्षीय लीलाधर कुशवाहा को एम्स भोपाल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उनकी एमएलसी बनाई गई है। मेडिकल दस्तावेज में 10-12 लोगों के समूह द्वारा हमले का उल्लेख है। घटना शनिवार रात करीब 10:45 बजे की बताई गई है। एक अन्य युवक भी घायल हुआ, जिसका उपचार कराया गया।

**ड्यूटी से लौटते समय बदमाशों ने किया हमला-** घायल लीलाधर ने बताया

कि वह अपने तीन दोस्तों के साथ मंडीदीप फैक्ट्री से ड्यूटी खत्म कर राजपूत भवन के पास से पैदल जैन ब्रदर्स होटल खाना खाने जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार और लहराते हुए बाइक चला रहे कुछ युवकों ने उन्हें टक्कर मार दी।

विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट करने लगे। जान बचाने के लिए चारों युवक होटल के अंदर घुस गए। इसके कुछ ही मिनट बाद 10-15 बदमाश हथियार लेकर होटल में आ धमके और हमला शुरू कर दिया।

पीड़ित का आरोप है कि बदमाशों ने पहले होटल के अंदर हमला किया, फिर उसे घसीटकर बाहर ले गए और गर्दन समेत शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर धारदार हथियारों से कई वार किए। मेडिकल रिपोर्ट में धारदार हथियार से गहरे घाव दर्ज हैं। पीड़ित का कहना है कि यदि उसने बचाव नहीं किया होता तो उसकी जान जा सकती थी।

# देखो राहुल, अखिलेश, दिग्गी; राम का नाम बदनाम ना करो : राकेश शर्मा

**भोपाल।** सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं ने 500 वर्ष इंतजार किया तब राम मंदिर का निर्माण हुआ। कुछ धन पशुओं ने भगवान के चढ़ावे में गड़बड़ी की जिसकी सजा कानून और ऊपर वाला दोनों उन्हें देंगे। पर आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि वह लोग जो लगातार राम मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे थे वह आज सामने निकलकर फिर राम और राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को आज राम मंदिर की चिंता हो रही है वह अखिलेश यादव जिनके पिता मुलायम सिंह यादव ने निर्दोष, निरीह, निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थीं जिसमें कई निर्दोष कारसेवकों की जान चली गई थी। आश्चर्य इस बात पर होता है कि जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था तो कांग्रेस के प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड़ा, अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर के भव्य कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया था। वोटों की राजनीति के लिए हमेशा राम के खिलाफ खड़े रहने वाले यह विपक्ष के

नेता आज फिर अपनी वोटों की रोटियां सेकने के लिए आज फिर मैदान में उतरे हुए हैं। सनातन धर्म का विरोध यह विपक्ष के नेता हमेशा से करते आ रहे हैं और जो सनातन धर्म के विरोधी हैं उनका पोषण और संरक्षण भी यह विपक्ष के नेता हमेशा से करते आ रहे हैं। जब राम मंदिर का विवाद कोर्ट में चल रहा था तो वहां तात्कालिक कांग्रेस सरकार ने राम को काल्पनिक पात्र कहा था। कोई विपक्ष का नेता वह टॉयलेट निर्माण की बात कर रहा था, कोई वहां लाइब्रेरी, स्कूल खोलने की बात कर रहा था। मंदिर निर्माण से लाखों करोड़ों विश्व में सनातन धर्म को मानने वालों की आस्था से खिलावाड़ करने का और अपमान करने का कोई भी मौका इन विपक्ष के दल के नेताओं ने नहीं छोड़ा था। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी वह लगातार हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ



कानून बनाने का काम कर रही थी, लोग आज भी इसे नहीं भूलें हैं कि किस तरह इंदिरा गांधी ने करपात्री महाराज के नेतृत्व में गायों की रक्षा के लिए किए जा रहे आंदोलन में दिल्ली में गोलियां चलवाई थीं जिसमें कई मासूम साधु-संतों के प्राण चले गए थे। बाबरी के ढांचे के गिरने के बाद यह विपक्ष के नेता वहां फिर से मस्जिद निर्माण की वकालत करते रहे। सनातन हिंदू धर्म को कभी डेंगू, मलरिया बताने वाले यह विपक्ष के नेता आज एक सुर में राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ एवं विश्व हिंदू परिषद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ एवं विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि उनके अथक प्रयासों से आज मंदिर का निर्माण हो पाया है। उनके खिलाफ जनता में बेसिर पैर के आरोप लगा रहे हैं। वह नहीं जानते की 500 वर्ष का जो इंतजार सनातन धर्म के

मानने वाले मंदिर निर्माण का कर रहे थे उसको पूरा करने का काम आज नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ संघ और विश्व हिंदू परिषद ने किया है। मुस्लिम तुष्टिकरण और चंद बोटों की खातिर अपनी घटिया मानसिकता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड़ा अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल दिखा रहे हैं। इससे दो कदम आगे चलते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपना चंदा वापस मांग रहे हैं साथ ही उज्जैन से अयोध्या तक पदयात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। क्या दिग्विजय सिंह यह बता सकते हैं कि जब राम को काल्पनिक पात्र कहा जा रहा था तब दिग्विजय सिंह कौन सी गहरी नींद में सोए हुए थे? तब उनको अपनी आस्था और विश्वास जिसे वह राम में आज व्यक्त कर रहे हैं तब क्यों नहीं याद आई थी? हजारों लाखों लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में भाग लेकर आज अपने राम के शोध मंदिर को प्राण किया है तो इन विपक्ष के नेताओं को आज भी भव्य राम मंदिर का निर्माण पच नहीं पा रहा है।



**MPIDC**  
MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT  
CORPORATION LTD.



**इन्वेस्ट**  
मध्यप्रदेश

प्रदेश का  
सबसे बड़ा  
कन्वेंशन सेंटर  
एवं उद्योग,  
निवेश,  
नवाचार और  
रोज़गार का  
नया केंद्र

# मध्यप्रदेश की औद्योगिक प्रगति की नई पहचान



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

## सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भूमिपूजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा

6 जुलाई, 2026 | सतगढ़ी, भोपाल

### प्रदेश का सबसे अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, उद्योग प्रदर्शनी,  
निवेशक सम्मेलन एवं बायर-सेलर मीट  
का नया वैश्विक मंच

### स्मार्ट औद्योगिक इकोसिस्टम

70 हेक्टेयर में एकीकृत  
औद्योगिक परिसर, आधुनिक अधोसंरचना  
एवं विश्वस्तरीय सुविधाएं

### भविष्य के उद्योगों के लिए स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर

जल प्रबंधन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट,  
एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ईवी चार्जिंग  
एवं आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था

### 15,000+ रोज़गार के अवसर

गारमेंट्स, टॉयज़ एवं आईटी आधारित  
उद्योगों में बड़े पैमाने पर  
प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार

### सुगम कनेक्टिविटी

राजा भोज एयरपोर्ट एवं  
रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक  
रोड संपर्क

### 'वर्क-लिव-गो' मॉडल

औद्योगिक, वाणिज्यिक, लॉजिस्टिक्स,  
आवासीय सहयोगी सुविधाओं एवं  
हरित क्षेत्रों से युक्त औद्योगिक-शहरी विकास

सीधा प्रसारण



@Cmmadhyapradesh / @jansampark.mathyapradesh



@Cmmadhyapradesh / @jansamparkMP



jansamparkMP